घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 177- बुधवार 29 - अप्रैल 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

प्रधानमंत्री ने काशी को दी 6332 करोड़ की 163 परियोजनाओं की बड़ी सौगात.....

महिलाओं को सपा-कांग्रेस ने धोखा दिया...परिवारवाद में डूबे दल

नारी शक्ति से डरे हैं,मैं आरक्षण दिलाकर रहूंगा : पीएम मोदी

वाराणसी,28 अप्रैल 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 6332 करोड़ रुपये की 163 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों–बनारस से पुणे (हडपसर) और अयोध्या से मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस) को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को काशी में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, 40 साल से महिला आरक्षण लटका था। हमने 2023 में नारी शक्ति अभिनंदन पारित किया। ये कानून लागू हो,इसके लिए चर्चा रखी। सपा, कांग्रेस, टीएमसी,डीएमके जैसी पार्टियों को देश की महिलाओं को धोखा दिया। ऐसे दलों ने 40 साल से महिला आरक्षण पर ब्रेक लगा दिया। सपा ने फिर से इसे लाल झंडी दिखा दी। असली बात यह है कि ये सारे परिवारवादी और तुष्टिकरण में डूबे दल नारी शक्ति से डरे हैं। ये परिवारवादी डर, देश की बेटियों को विधानसभा ससंद नहीं आने देना चाहता है। पीएम मोदी ने कहा...मैं आप सभी बहनों को फिर से भरोसा देता हूं कि आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोडूंगा।

परिवारवादी पार्टियां देश की बेटियों को संसद-विधानसभाओं में नहीं आने देना चाहतीं

पीएम मोदी ने कहा...बेटियों के लिए थल-वायु और नभ सेना में नए अवसर मिले हैं। डिफेंस के दरवाजे भी बेटियों के लिए खोले हैं। भाजपा सरकार का मतलब ही यही है नारी का उत्थान। हर मोर्चे पर भारत की बेटियां अच्छा काम कर रही हैं। बेटियों की भूमिका बढ़नी चाहिए। देश को इसकी जरूरत है। देश की नई संसद बनाने के पीछे भी बहनों की भागीदारी का विचार था। 40 साल से महिला का आरक्षण लटका था। हमने 2023 में नारी शक्ति अभिनंदन पारित किया। ये कानून लागू हो, इसके लिए चर्चा रखी। सपा,कांग्रेस,टीएमसी,डीएमके जैसी पार्टियों को देश की महिलाओं को धोखा दिया। ऐसे दलों ने 40 साल से महिला आरक्षण पर ब्रेक लगाया था। सपा ने फिर से इसे लाल झंडी दिखा दी है। असली बात यह है कि ये सारे परिवारवादी और तुष्टिकरण में डूबे दल नारी शक्ति से डरे हैं। आप सभी से डरे हैं। ये परिवारवादी डर,देश की बेटियों को विधानसभा-ससंद नहीं आने देना चाहते हैं।

पीएम मोदी बोले- वाराणसी बढ़ेगा, डेयरी बढ़ेगी तो बोनस भी बढ़ता जाएगा

पीएम मोदी ने कहा, भारतीय न्याय संहिता ने भी बेटियों को सुरक्षा का भरोसा दिया है। गंभीर अपराधों में तेजी से फैसले आने लगे हैं। ऐसे कदम बेटियों को सुरक्षा की गारंटी देते हैं। महिलाओं की जब आर्थिक शक्ति बढ़ती है तो घर में उनकी आवाज भी बुलंद हो जाती है। 11 साल में 10 करोड़ बहनें सेल्फ हेल्थ समूह में जोड़ी गई हैं। बहनें अपना काम कर रही हैं। 3 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं। लखपति दीदी अभियान को गति देने में हमारे डेयरी सेक्टर की बड़ी भूमिका है। बनारस डेयरी में लाखों बहनें काम कर रही हैं। इनको बोनस के तौर पर 106 करोड़ रुपए सीधे मिले हैं। मैं काशी में डेयरी सेक्टर से जुड़ी बहनों से कहूंगा कि अभी तो शुरुआत हुई है। वाराणसी बढ़ेगा, डेयरी बढ़ेगी तो बोनस भी बढ़ता जाएगा।

यूपी में सपा सरकार थी,बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था : पीएम मोदी ने कहा- साथियों, कमाई, पढ़ाई और दवाई के साथ पहली बार प्रॉपर्टी रजिस्ट्री हुई है। आज हमार माई बहन सही में अपनी घर की मलकिन बनत हैं। आपने यहां यूपी में आंखों के सामने हालात बदलते देखे हैं। जब यहां सपा की सरकार थी,बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। आज बेटियों के बारे में गलत सोच रखने वाला अच्छे से जानता है उसका अंजाम क्या होगा।

महिलाओं से पूछा नहीं जाता, सीधे फरमान सुना दिया जाता था:पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा...काशी की बहनों ने भी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना किया है। बेटियों को अक्सर सवालों के जवाब से गुजरना मिलता था। तू का करबो,तोहे का जरूरत है। तू चुप रह। ऐ काम तुमसे न हो पाई। कई बार तो सवाल भी नहीं पूछे जाते थे,सीधे फरमान सुनाया जाता था। ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। ऐसा सिर्फ काशी के लिए नहीं,देश की अधिकता बहन-बेटियों के ऐसे ही अनुभव रहे हैं। इसे सहज मान लिया जाता था। पीएम ने कहा, मैं जब 25 साल पहले गुजरात में सीएम बना था तो वहां ऐसी धारणाओं को तोड़ने का काम किया। वहां दो योजनाएं शुरू की। पहली स्कूल के लिए, दूसरी और उनकी फीस की मदद के लिए।

पीएम मोदी ने सिक्किम में खेला फुटबॉल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार थम जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। मंगलवार सुबह गंगटोक में उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिला,जब वे युवा खिलाड़ियों के बीच फुटबॉल मैदान में उतरे और उनके साथ खेलते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ फुटबॉल खेला, बल्कि गोल करने के बाद साथी खिलाड़ियों के साथ सेलिब्रेशन भी किया। इस दौरान की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा कीं। तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा कि 'सिक्किम में अपने युवा मित्रों के साथ गंगटोक की सुहानी सुबह में फुटबॉल खेलने जैसा कुछ नहीं। ' सिक्किम के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में भी फुटबॉल अत्यंत लोकप्रिय खेल है। विशेषकर कोलकाता जैसे शहर को भारत में क्लब फुटबॉल का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां जमीनी स्तर तक फुटबॉल क्लब सक्रिय हैं। विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री का फुटबॉल मैदान में उतरना और युवाओं के साथ खेलना, बंगाल के मतदाताओं को साधने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। फुटबॉल विश्व कप जैसे बड़े आयोजनों के दौरान पश्चिम बंगाल में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है, और कई बार सड़कों पर यातायात तक प्रभावित हो जाता है। ऐसे में इस खेल के माध्यम से जुड़ाव बनाना एक प्रतीकात्मक कदम माना जा रहा है।

अनिल अंबानी समूह की 3034 करोड़ की संपत्ति कुर्क

नई दिल्ली,28 अप्रैल 2026। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह (आरएएजी) की कंपनियों के खिलाफ जारी धनशोधन जांच के अंतर्गत 3,034.90 करोड़ रुपये की नई संपत्तियां जब्त की हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को जारी बयान में बताया कि ईडी ने मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 3,034.90 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। एजेंसी के मुताबिक कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई का एक फ्लैट, खंडाला का फार्महाउस, सानंद की जमीन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के 7.71 करोड़ शेयर शामिल हैं। इस तरह रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़े मामलों में अब तक 19,344 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। ईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियां रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर-इंफ्रा) की हैं। इनमें मुंबई में एक फ्लैट, खंडाला (महाराष्ट्र का एक हिल स्टेशन) में एक फार्महाउस, साणंद (अहमदाबाद) में कुछ भूखंड और आर-इंफ्रा के 7.71 करोड़ शेयर शामिल हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया है। ईडी ने कहा कि रिलायंस अनिल अंबानी समूह के खिलाफ मामलों में कुर्क की गई संपत्तियों की कुल राशि अब 19,344 करोड़ रुपये हो गई है। समूह के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी और धन के निर्धारित उद्देश्य से इतर उपयोग के आरोपों की ईडी द्वारा जांच की जा रही है।

चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड...आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली कोर्ट से जमानत

इंदौर,28 अप्रैल 2026। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या करने की आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने इसकी पुष्टि की है। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की आरोपी सोनम को हत्याकांड के 11 महीनों बाद अदालत से राहत मिली है। सोनम गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद थी। उसका प्रेमी राज भी शिलॉन्ग जेल में बंद है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी के साथ 23 मई 2025 को हनीमून पर मेघालय गए थे। यहां अचानक दोनों के गायब होने की खबर आई। कई दिनों की तलाश के बाद 2 जून को एक खाई में राजा रघुवंशी की लाश मिली थी तो हत्या करके फेंके जाने की बात सामने आई। हत्याकांड के कुछ दिनों बाद सोनम को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। सोनम रघुवंशी ने गिरफ्तारी के बाद हत्याकांड का खुलासा किया और बताया कि उसने अपने प्रेमी राज के साथ पति को मार डालने की साजिश रची थी। इसी के तहत वह राजा को शिलॉन्ग ले गई थी। इंदौर से ही गए राज के तीन दोस्तों के साथ मिलकर सोनम ने अपने हाथों से ही अपना सुहाग उजाड़ लिया था। पति को मारकर उसने खाई में फेंक दिया। राजा को धारदार हथियार से मारा गया था और पत्थर से भी वार किया गया था। सोनम और राज ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बेहद चालाकी के साथ पूरी साजिश रची थी। वह इस लूटपाट के दौरान हुई हत्या के रूप में दिखाना चाहते थे। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सोनम बड़ी चालाकी से वहां से भाग निकली थी। इंदौर आकर उसने प्रेमी के साथ मुलाकात भी की और फिर जब तीन आरोपी पकड़े गए तो उसे अपनी गिरफ्तारी का अंदाजा हो गया और वह आखिरकर यूपी में पकड़ी गई

गुजरात की सभी 15 महानगरपालिकाओं में भाजपा ने अपना परचम लहराया...

अहमदाबाद,28 अप्रैल 2026। गुजरात की सभी 15 महानगरपालिकाओं के चुनाव में इस बार भी भाजपा का दबदबा कायम रहा। सूरत महानगरपालिका में भाजपा ने एक बार फिर प्रचंड जीत दर्ज करते हुए 120 में से 115 सीटों पर कब्जा कर लिया है। पिछले 30 वर्षों से जारी भाजपा का एकछत्र शासन अगले पांच वर्षों तक भी बरकरार रहेगा। वर्ष 2021 में 27 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी इस बार मात्र 4 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस, जो पिछली बार खाता भी नहीं खोल सकी थी, इस बार केवल 01 सीट जीतने में सफल रही है। इन चुनावों का आयोजन एसआईआर(स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) प्रक्रिया और 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद हुआ। हालांकि, इन

बदलावों के बावजूद मतदान प्रतिशत में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई। राज्यभर में 49 लाख से अधिक मतदाता मतदान के लिए बाहर ही नहीं निकले। मतदान प्रतिशत की बात करें तो वापी महानगरपालिका में पहली बार हुए चुनाव में सबसे अधिक 72.29 फीसद मतदान दर्ज किया गया, जबकि गांधीधाम में सबसे कम 46.03 फीसद मतदान हुआ। राज्य की सभी 15 महानगरपालिकाओं में भाजपा ने अपना परचम लहराया है। विपक्ष को केवल नाममात्र की सीटों से संतोष करना पड़ा। चुनाव से पहले कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे, लेकिन इसका असर मतदान या परिणामों पर नजर नहीं आया। 15 महानगरपालिकाओं में से अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर और जामनगर पुरानी महानगरपालिकाएं हैं, जबकि महेसाणा, सुरेंद्रनगर, आनंद, मोरबी, नडियाद, वापी, नवसारी, पोरबंदर और गांधीधाम नई महानगरपालिकाएं हैं, जहां पहली बार चुनाव हुए हैं। अहमदाबाद महानगरपालिका के खाड़िया वार्ड में, जो भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है, कांग्रेस ने जीत दर्ज कर भाजपा को झटका दिया है। यहां भाजपा के चारों उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है। उल्लेखनीय है कि गुजरात में 15 नगर निगमों, 84 नगरपालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों के लिए रविवार को वोटिंग हुई थी और आज इन चुनावों के नतीजे जारी हुए हैं। अभी नगरपालिकाओं, जिला पंचायत और तालुका पंचायतों का पूर्ण विवरण आना शेष है।

मृत बहन का कंकाल कंधे पर लादकर बैंक पहुंचा भाई,बोला...अब तो पैसे दे दो'

ओडिशा,28 अप्रैल 2026। ओडिशा के क्योंझर जिले से इंसानियत और व्यवस्था दोनों को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक गरीब भाई अपनी मृत बहन के बैंक खाते में जमा 20 हजार रुपये निकालने के लिए इतना मजबूर हो गया कि वह बहन का कंकाल कंधे पर उठाकर बैंक पहुंच गया। इस घटना ने सिस्टम की संवेदनहीनता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना ब्लॉक के डियानाली गांव निवासी जीतू मुंडा की बहन कलरा मुंडा का करीब दो महीने पहले निधन हो चुका था। परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और बहन के खाते में जमा 20 हजार रुपये उनके लिए सहारा बन सकते थे। लेकिन जब जीतू बैंक पहुंचा, तो उसे नियमों का हवाला देकर लौटा दिया गया–कहा गया कि खाता धारक के बिना पैसे नहीं दिए जा सकते। बार-बार चक्कर काटने और कहीं से मदद न मिलने

पर जीतू का धैर्य टूट गया। वह सीधे श्मशान पहुंचा, जहां उसकी बहन को दफनाया गया था। वहां से उसने बहन का कंकाल निकाला और उसे कंधे पर उठाकर करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंच गया। बैंक के बाहर यह दृश्य देखकर लोग स्तब्ध रह गए। जीतू का दर्द साफ था वह सिस्टम से पूछ रहा था, 'ये रही मेरी बहन... अब तो पैसे दे दो।' यह घटना सिर्फ एक परिवार की मजबूरी नहीं, बल्कि उस कठोर व्यवस्था का आईना है, जहां नियम इंसानियत पर भारी पड़ जाते हैं।

तुर्की से भारत लाया गया दाऊद का सबसे खास गुर्गा, 5000 करोड़ के ड्रग सिंडिकेट वाले सलीम डोला का अब होगा 'हिसाब'

नई दिल्ली,28 अप्रैल 2026। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बेहद करीबी और कुख्यात ड्रग माफिया सलीम डोला के बुरे दिन आखिरकार शुरू हो गए हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक बड़े और बेहद गोपनीय ऑपरेशन को अंजाम देते हुए डोला को तुर्की से भारत डिपोर्ट करवा लिया है। आज सुबह एक विशेष विमान के जरिए इस खूंखार माफिया को दिल्ली के टेक्निकल एयरपोर्ट पर लाया गया। बता दें कि हाल ही में तुर्की के इस्तांबुल में सुरक्षा एजेंसियों ने उसे दबोचा था, जिसके बाद से ही उसे भारत लाने की तैयारियां तेज हो गई थीं।

दुबई से तुर्की तक फैला था मौत के सौदागर का जाल

सलीम डोला कोई छोटा-मोटा अपराधी नहीं है, बल्कि वह दुबई और तुर्की जैसे देशों में बैठकर भारतीय युवाओं की रगों में जहर (ड्रग्स) घोलने का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चला रहा था। वह लंबे समय से भारत से फरार था और विदेशों में छिपकर अपना काला धंधा बढ़ा रहा था। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर इस मौत के सौदागर को पकड़ने के लिए एक

बड़ा जाल बिछाया था,जो अंततः सफल रहा। फिलहाल,खुफिया एजेंसियां दिल्ली में डोला से कड़ी पूछताछ कर रही हैं,जिसके बाद इस माफिया को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मुंबई पुलिस या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हवाले कर दिया जाएगा।

5,000 करोड़ का काला कारोबार और दाऊद का 'आशीर्वाद' : इस कुख्यात ड्रग माफिया के तार सीधे तौर पर दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी और उसके खौफनाक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। वह भारत में ड्रग्स सप्लाई का एक अहम चैनल संभालता था। ग्लोबल सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क की दुनिया में सलीम डोला का नाम बहुत बड़ा माना जाता है। जांच एजेंसियों की मानें तो दाऊद के इशारों पर काम करने वाला यह तस्कर सालाना 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के ड्रग्स का काला कारोबार कर रहा था।

बंगाल चुनाव : दूसरे एवं अंतिम चरण में 142 सीटों पर वोटिंग आज...1,448 उम्मीदवार मैदान में

कोलकाता,28 अप्रैल 2026। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के अंतर्गत राज्य की 142 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार को मतदान होगा। अंतिम चरण में राजधानी कोलकाता के अलावा उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, नदिया और पूर्व बर्धमान जिलों में मतदान कराए जाएंगे। इस चरण में 1,448 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने सभी 142 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 141 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक,दूसरे चरण के लिये 1463 नामांकन प्राप्त हुए। इनमें 15 लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। दक्षिण 24 परगना के भांगड़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 19 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सबसे कम पांच

उम्मीदवार हुगली की गोघाट (एससी) सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में 8 जिलों के कुल 3,21,73,837 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 1,64,35,627 पुरुष तथा 1,57,37,418 महिला मतदाताओं के अलावा 792 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। इस चरण में कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट पर सबकी नजरें टिकी है जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से है। वर्ष 2021 के चुनाव में नंदीग्राम में दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था, जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की थी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिये चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। लगभग सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और संवेदनशील व अति-संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। वेबकास्टिंग, सीसीटीवी निगरानी और लगातार फ्लैग मार्च के जरिए शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग सूत्रों के अनुसार, सबसे अधिक उत्तरी 24 परगना जिले में कुल 507 कंपनियां तैनात की जा रही हैं।

धर्म पूछा,कलमा पढ़ने को कहा,फिर चाकुओं से गोदा

मुंबई में दो गाईस पर हमला,फडणवीस बोले-यह जिहाद,एटीएस ने कहा...आतंकी हमला

मुंबई,28 अप्रैल 2026। मुंबई के मीरा रोड स्थित नया नगर इलाके में एक युवक ने दो सिक्योरिटी गार्ड्स से उनका धर्म पूछने के बाद चाकू से हमला कर दिया। आरोपी की पहचान 31 साल के जैब जुबेर अंसारी के रूप में की गई है। घटना सोमवार सुबह करीब 4 बजे हुई। पुलिस के अनुसार, एक अंडर

कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास दो सिक्योरिटी गार्ड, राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो रमेश सेन ड्यूटी पर तैनात थे। आरोपी पहले इलाके में आया और मस्जिद का रास्ता पूछा। कुछ समय बाद वह दोबारा लौटा। उसने एक गार्ड से धर्म पूछने के बाद अचानक चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद वह केबिन में घुसा और दूसरे गार्ड से कलमा पढ़ने को कहा। जब गार्ड ऐसा नहीं कर पाया, तो उस पर भी हमला कर दिया गया। दोनों घायल गार्डों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आरोपी जिहाद के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाना चाहता था।

संपादकीय

परिवर्तन को तैयार दिखता बंगाल

बंगाल सिर्फ वोट नहीं डाल रहा है। वह अपने लोकतांत्रिक भविष्य की नई दिशा भी तय करता दिख रहा है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के सघन संशोधन का जो अभियान चलाया,उससे राज्य भर से बड़े पैमाने पर संदिग्ध,मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया का सख्त और पारदर्शी होना केवल मतदान तक सीमित नहीं है। यह उस औपचारिक राज्य की वापसी है,जो लंबे समय तक स्थानीय शक्ति संरचनाओं के पीछे छिप गया था। मतदाता परिणाम और सुशासन के आधार पर सत्ता की वैधता तय करना चाहता है। राजनीति विज्ञान का एक सीधा नियम है कि जहां अनौपचारिक शक्ति संरचनाएं और सिंडिकेट हावी होते हैं,वहां राज्य की औपचारिक क्षमता पूरी तरह कमजोर हो जाती है। यही स्थिति बंगाल में निवेश और विकास की सबसे बड़ी बाधा बन गई है। जो बंगाल कभी औद्योगिक उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, वह आज रोजगार देने में काफी पिछड़ चुका है। जब भी कोई नया कारखाना या उद्यम शुरू होता है, स्थानीय बाहुबली उसमें दखल देते हैं। इससे निवेशक पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। जनता अब ऐसा तंत्र चाहती है, जो पारदर्शी हो और औपचारिक अर्थव्यवस्था को मजबूती दे।

यह चुनाव एक गहरे सामाजिक और पीढ़ीगत बदलाव का भी गवाह बन रहा है। नई पीढ़ी राजनीतिक निष्ठा के बजाय अवसरों के आधार पर प्राथमिकताएं तय कर रही है। आज का युवा मतदाता पारंपरिक झंडों और नारों का मोहताज नहीं है। उसे एक ऐसा तंत्र चाहिए जिस पर वह विश्वास कर सके। वह बेंगलुरु, पुणे या दिल्ली जैसी सुविधाओं और अवसरों को अपने ही राज्य में देखना चाहता है। जब यह महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती तो उसका गुस्सा सत्ता के खिलाफ मुखर होता है। राष्ट्रवाद,पारदर्शिता और विकास की राजनीति का जो नया विकल्प राज्य में उभर रहा है,वह इसी युवा वर्ग की आकांक्षाओं को स्वर देता दिख रहा है। राजनीति में नागरिक और सरकार के रिश्ते के मायने भी तेजी से बदल रहे हैं।

सरकार की मुफ्त राशन और नकद सहायता जैसी योजनाओं ने समाज के निचले तबके को फौरी राहत जरूर दी है,लेकिन अर्थशास्त्र और राजनीति का यह अनुभव बताता है कि एक सीमा के बाद कल्याणकारी योजनाओं का राजनीतिक प्रभाव घटने लगता है। खासकर तब,जब वे जनता की नई आकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर पातीं। जब सरकार नागरिकों को स्थायी रूप से केवल'लाभार्थी' मानकर चलने लगती है तो बुनियादी विकास पीछे छूट जाता है। यह निर्भरता समाज को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देती। बंगाल का मतदाता अब कुछ सौ रुपयों की मासिक सहायता से आगे पक्का रोजगार और अपनी मेहनत का सम्मानजनक मोल चाहता है। सशक्तीकरण का यही माडल अब बंगाल के विमर्श में जगह बनाता प्रतीत हो रहा है।

जनसांख्यिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा ऐसी चिंताएं बन चुकी हैं, जिन्हें अब किसी भी कीमत पर अनदेखा नहीं किया जा सकता। सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ के आरोप और उनसे जुड़ी चिंताओं ने राज्य की सामाजिक पहचान पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। संदेशखाली जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सत्ता के करीब माने जाने वाले स्थानीय बाहुबलियों ने जिस प्रकार महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई, उसने बंगाली भद्रलोक और ग्रामीण समाज को भीतर तक आहत किया। यह एक विशेष प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति का सीधा नतीजा है। राज्य का एक वर्ग कह रहा है कि इस तरह की नीतियों में कानून के समान शासन की पूरी तरह अनदेखी हो रही है।

एक देश,एक पाठ्यक्रम: संघीयता का संकट या शिक्षा क्रांति?

डॉ. सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणा

रुकने वालों का इतिहास नहीं होता...एक देश एक पाठ्यक्रम शिक्षा के नाम पर लूट का विरोध जारी रहना चाहिए...यह वाक्य आज भारतीय शिक्षा व्यवस्था में चल रहे सबसे बड़े विमर्श को सटीक रूप से सामने रखता है...राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रस्तावित एक देश, एक पाठ्यक्रम का विचार देशभर में तीखी बहस का विषय बन चुका है...अप्रैल 2026 तक स्थिति यह है कि तमिलनाडु,केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इसे अपनी संवैधानिक स्वायत्तता पर आघात मानते हुए इसका विरोध कर रहे हैं,जबकि केंद्र सरकार इसे शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और एकरूपता स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है...ऐसे में सवाल उठता है... क्या यह पहल वास्तव में शिक्षा सुधार की दिशा में क्रांति है, या फिर संघीय ढांचे पर दबाव डालने का प्रयास?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव का खाका प्रस्तुत किया। 34 वर्षों से चली आ रही 1986 की नीति को बदलते हुए यह नई संरचना–5+3+3+4–लेकर आई, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक स्तर तक शिक्षण को अधिक लचीला और समावेशी बनाया गया है। इसमें 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा, 8 से 11 के लिए प्राथमिक, 11 से 14 के लिए उच्च प्राथमिक और 14 से 18 वर्ष तक के लिए माध्यमिक शिक्षा निर्धारित की गई है। मातृभाषा में शिक्षा, बहुभाषिकता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता को इसमें प्रमुखता दी गई है।

एक देश, एक पाठ्यक्रम का मूल आधार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में एक न्यूनतम शैक्षिक मानक स्थापित करना है। हालांकि इसमें 30 प्रतिशत तक लचीलापन दिया गया है ताकि राज्य अपनी सांस्कृतिक और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन कर सकें। लेकिन विरोध करने वाले राज्यों का मानना है कि यह लचीलापन केवल प्रतीकात्मक है और असल में यह एक केंद्रीकृत पाठ्यक्रम थोपने का प्रयास है।

संविधान के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों की इसमें भूमिका है। ऐसे में राज्यों का आरोप है कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं–जैसे समग्र शिक्षा अभियान–के तहत मिलने वाले फंड को रोककर दबाव बना रही है। तमिलनाडु इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां हजारों करोड़ रुपये की राशि रोकी गई। राज्य सरकार ने इसे अपनी नीतिगत स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए इसका विरोध किया। इस विवाद का एक बड़ा पहलू भाषाई और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है। दक्षिण भारत के कई राज्य हिंदी को थोपे जाने वाली भाषा के रूप में देखते हैं,जबकि केंद्र

का कहना है कि त्रि-भाषा सूत्र में किसी एक भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। इसके बावजूद यह आशंका बनी हुई है कि एक समान पाठ्यक्रम से क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य की उपेक्षा होगी। उदाहरण के तौर पर,तमिलनाडु की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत या बंगाल का साहित्यिक योगदान एक मानकीकृत पाठ्यक्रम में सीमित हो सकता है।

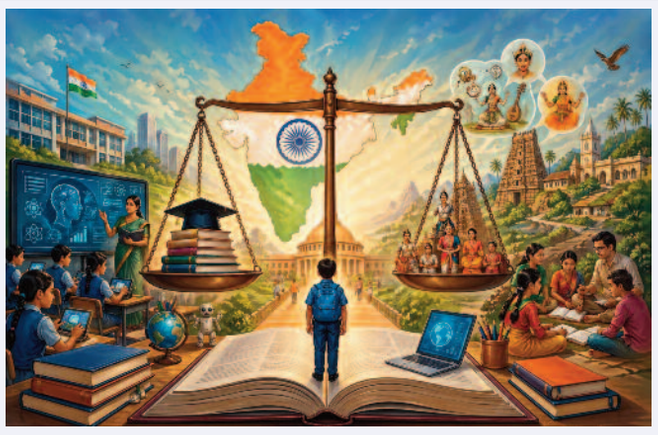

केंद्र सरकार का तर्क है कि यह नीति शिक्षा में असमानताओं को कम करेगी। वर्तमान में भारत की शिक्षा व्यवस्था में भारी अंतर दिखाई देता है–जहां एक ओर निजी स्कूलों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलती है,वहीं सरकारी स्कूलों में संसाधनों की कमी के कारण परिणाम कमजोर रहते हैं। एक देश,एक पाठ्यक्रम के माध्यम से एक समान गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है,ताकि देश के हर बच्चे को समान अवसर मिल सके।
इसके साथ ही,यह नीति कौशल-आधारित शिक्षा पर जोर देती है। कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस जैसे विषयों को प्रारंभिक स्तर से जोड़ने का प्रस्ताव है, जो भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखता है। यह पहल भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

हालांकि आलोचक इसे शिक्षा के नाम पर लूट भी करार देते हैं। उनका कहना है कि इससे शिक्षा का निजीकरण बढ़ेगा और कोचिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। कोटा जैसे शहरों में पहले से ही कोचिंग का बड़ा बाजार है, और एक समान परीक्षा प्रणाली इसे और मजबूत कर सकती है। वहीं,केंद्र का मानना है कि एकीकृत प्रवेश परीक्षा पारदर्शिता बढ़ाएगी और भ्रष्टाचार को कम करेगी।
ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो भारत में शिक्षा सुधार हमेशा विवादों के साथ जुड़े रहे हैं। अंग्रेजों के समय मैकाले की शिक्षा नीति से लेकर कोठारी आयोग तक, हर बदलाव ने बहस को जन्म दिया। लेकिन यह भी सच है कि बिना सुधार के प्रगति संभव नहीं है।
अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों से भी यह स्पष्ट होता है कि एकरूपता और विकेंद्रीकरण दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। फिनलैंड जैसे देशों ने एक समान शिक्षा प्रणाली अपनाकर उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए हैं, जबकि अमेरिका जैसे देशों में विकेंद्रीकृत प्रणाली के कारण असमानता बनी हुई है। भारत को अपनी विविधता और जनसंख्या के अनुरूप संतुलित मॉडल अपनाना होगा।
राजनीतिक स्तर पर यह मुद्दा अब केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रह गया है। यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन का प्रश्न बन गया है। जहां एक ओर कुछ राज्य इसे अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं अन्य राज्य इसे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए चुनौती दे रहे हैं। भविष्य की दृष्टि से देखें तो भारत के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। डिजिटल युग में प्रतिस्पर्धा के लिए एक मजबूत और आधुनिक शिक्षा प्रणाली आवश्यक है। यदि राज्य और केंद्र के बीच टकराव जारी रहता है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान छात्रों को होगा। शिक्षा में सुधार के लिए संवाद, सहयोग और संतुलन आवश्यक है।

अंततः यह समझना जरूरी है कि एक देश, एक पाठ्यक्रम केवल एक नीति नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है–एक ऐसा प्रयास जिसमें पूरे देश को एक समान शैक्षिक आधार देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसे लागू करने का तरीका लोकतांत्रिक और सहमति-आधारित होना चाहिए।

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में शिक्षा का कोई भी मॉडल तभी सफल हो सकता है जब वह स्थानीय जरूरतों और राष्ट्रीय लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए। केंद्र को चाहिए कि वह राज्यों के साथ संवाद बढ़ाए और उनकी चिंताओं को समझे, वहीं राज्यों को भी बदलाव के प्रति खुला दृष्टिकोण अपनाना होगा।

यदि हम इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठकर देखें,तो यह स्पष्ट होगा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि एक सक्षम और जागरूक नागरिक बनाना है। और यह लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब हम मिलकर आगे बढ़ें। समय की मांग है कि टकराव नहीं, संवाद को प्राथमिकता दी जाए। यदि भारत इस संतुलन को साधने में सफल होता है, तो आने वाला दशक वास्तव में शिक्षा क्रांति का होगा। अन्यथा, असमानता और विवाद हमारे भविष्य को प्रभावित करते रहेंगे।

पक्षियों के लिए पानी : एक बूंद जिंदगी की,एक सकोरा उम्मीद का

अंजनी सक्सेना
भोपाल मध्यप्रदेश

गर्मी का मौसम आते ही धरती तपने लगती है। इंसान पंखे,कूलर,एसी और ठंडे पानी का इंतजाम कर लेता है, पर क्या कभी सोचा है कि आसमान में उड़ने वाले उन बेजुबान परिंदों का क्या होता होगा,जिनके पास न घर है,न फ्रिज, न नल। उनके लिए तालाब सूख जाते हैं, नदियां दूर हो जाती हैं,और पेड़ भी अब शहरों में गिनती के बचे हैं। ऐसे में एक मिट्टी का बर्तन, उसमें भरा ठंडा पानी, उनके लिए किसी अमृत से कम नहीं होता। पक्षियों के लिए पानी रखना केवल दया का काम नहीं,प्रकृति के संतुलन और हमारी प्राचीन संस्कृति का भी हिस्सा है, जहां हर एक जीव को समान महत्व दिया गया है।।

इंसान तीन दिन बिना खाने के रह सकता है,पर बिना पानी के नहीं। पक्षियों का शरीर भी 60-70 प्रतिशत पानी से बना होता है। गर्मियों में तापमान 45 डिग्री पार कर जाता है, तब उनके शरीर से पानी तेजी से वाष्प बनकर उड़ता है।

वैज्ञानिकों का मानना है कि एक छोटी चिड़िया का मेटाबॉलिज्म इंसान से 10 गुना तेज होता है। यानी उन्हें हर 15-20 मिनट में पानी की जरूरत पड़ती है। अगर 2-3 घंटे पानी न मिले,तो डिहाइड्रेशन से उनकी मौत हो सकती है। कबूतर,मैना,गौरैया, कौआ, सबको उड़ान भरने,पंखों को साफ रखने,खाना पचाने और अंडे देने के लिए पानी की आवश्यकता होती है।

एक समय हर घर के आंगन में फुदकने वाली गौरैया आज लुप्त होने की कगार पर है। इसकी एक बड़ी वजह पानी और दाने की कमी है। शहरों में अब जो गौरैया बची हैं,वो अक्सर आपकी छत पर रखे पानी के बर्तन पर ही निर्भर हैं। पहले गांव-शहर सब जगह जोहड़, तालाब, कुएं होते थे। पक्षी वहीं से प्यास बुझाते थे। अब कंक्रीट के जंगल में न तालाब बचे,न पोखर। बिल्डिंगें इतनी ऊंची हो गई हैं कि बारिश का पानी भी जमीन तक नहीं पहुंचता।

अपने आसपास ही देखें तो पिछले 20 साल में शहरी इलाकों में अधिकांश जल स्रोत खत्म हो गए। कुएं,बावड़ी तो अब सूख ही गए हैं। मेरे घर के आसपास चार कुएं थे,जिनसे आसपास के लोग पानी भरा करते थे। गाय,कुत्ते और छोटे छोटे पंछी यहां पानी पीने आते थे। लेकिन अब हर घर में नल और बोरिंग के चलते सारे कुओं के पाट सूखे पड़े हैं। नतीजा गर्मियों में सैकड़ों पक्षी डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक से मर जाते हैं। मई-जून में पेड़ों के नीचे मरे हुए कबूतर,तोते,मैना मिलना आम बात हो गई है। कौआ और चील जैसे पक्षी तो फिर भी कचरे के ढेर से नमी पा लेते हैं, पर तोता,बुलबुल,गौरेया जैसी नाजुक चिड़ियाएं भी हैं जिन्हें दो बूंद पानी की बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं।

पक्षियों को पानी पिलाना केवल पुण्य कमाना ही नहीं है,अपना ही भविष्य भी सुरक्षित करना है। ये पक्षी पर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पक्षी फूलों का पराग एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। बीज खाकर उसे दूर-दूर तक गिराते हैं। इसी से नए पेड़ उगते हैं। अगर पक्षी प्यास से मरेंगे, तो जंगल नहीं बनेंगे, और जंगल नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी।

एक अकेली गौरैया दिन भर में सैकड़ों कीड़े खाती है। अगर गौरैया न हो, तो फसलों को कीड़े चट कर जाएंगे। तब किसान ज्यादा कीटनाशक डालेगा, जो फिर हमारे खाने में आएगा।

गिद्ध, चील, कौआ मरे हुए जानवरों को खाकर बीमारी फैलने से रोकते हैं। ये सब जिंदा रहें,इसके लिए पानी पहली शर्त है। कुल मिलाकर पक्षियों को बचाना मतलब खेती,हवा,पानी और अपना स्वास्थ्य बचाना है।

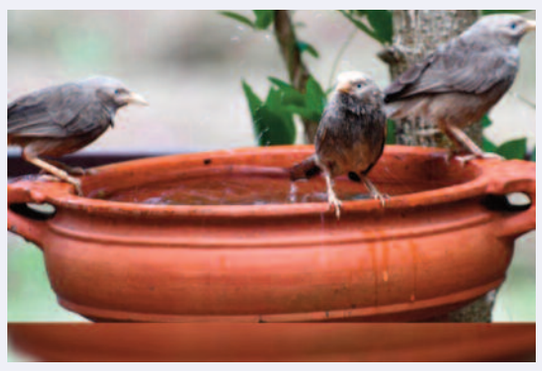

हमारे देश में तो 'जीव दया' संस्कारों में ही रची बसी है। जैन धर्म में 'पक्षी चबूतरे' बनाने की परंपरा है। हिंदू धर्म में सुबह-सुबह चिड़ियों को दाना-पानी देना शुभ माना जाता है। इस्लाम में भी बेजुबानों को पानी पिलाना सवाब का काम है।

हमारे दादा-दादी,नाना-नानी,गर्मी शुरू होते ही छत पर मिट्टी के सकोरे रख देते थे। यह मात्र एक परंपरा या अंधविश्वास नहीं, हजारों साल का अनुभव था। आज हम वातानुकूलित घरों और कार्यालयों में बैठकर वो अनुभव भूल गए। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने घर, दफ्तर या जहां पशु पक्षियों के लिए पानी रखना आसान हो वहां पानी रखे। इनके लिए पानी रखना सरल है पर सही तरीके से रखेंगे तो ज्यादा पक्षियों की जान बचेगी।

इसके लिए मिट्टी का चौड़े मुंह वाला बर्तन सबसे अच्छा है। मिट्टी पानी को ठंडा रखती है। प्लास्टिक गर्म हो जाता है और उसमें काई जल्दी लगती है। बर्तन 2-3 इंच गहरा हो ताकि छोटी चिड़िया डूबे नहीं।

इस बर्तन को छत,बालकनी, मुंडेर या पेड़ की डाल पर या ऐसी जगह जहां बिल्ली-कुत्ते न पहुंचें और धूप सीधी न आए वहां रख सकते हैं। छांव में पानी देर तक ठंडा रहता है। दो बर्तन रखें एक छांव में,एक धूप में क्योंकि कुछ पक्षी धूप में नहाना पसंद करते हैं।

याद से रोज थोड़ा समय निकालकर इस बर्तन का पानी बदलें। वरना मच्छर पनपेंगे और पक्षियों को बीमारी हो जाएगी। हफ्ते में एक बार बर्तन को खुरदुरे ब्रश से रगड़कर धोएं ताकि काई न जमे।

पानी के इस बर्तन के पास थोड़ा बाजरा,चावल के टुकड़े, ज्वार रख दें। गर्मी में पक्षियों को उड़ने की ऊर्जा चाहिए। पर ध्यान रहे नमकीन,तला-भुना या बासी खाना न डालें। वो उनके लिए जहर है। यदि आप किसी बड़े शहर में या किसी बड़ी सोसायटी में रहते हैं तो अपनी सोसाइटी में हर बिल्डिंग पर कम से कम दस बर्तन रखने का नियम बनाएं। ऑफिस की छत पर पानी रखने की जिम्मेदारी भी सामूहिक रुप से ली जा सकती है। शिक्षक अपने स्कूलों में बच्चों को प्रोजेक्ट दे सकते हैं।

इतना सब पढ़कर आप सोच रहे होंगे कि मेरे एक बर्तन से क्या होगा? तो उसका उत्तर है कि एक मिट्टी का बर्तन दिन में 20-30 पक्षियों की प्यास बुझाता है। 3 महीने की गर्मी में एक बर्तन 2000 से ज्यादा बार किसी की जान बचाता है।

आपका बच्चा जब बच्चा रोज छत पर पानी भरता है, तो उसके अंदर करुणा का बीज पड़ता है। वो सीखता है कि दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं है। वो जिम्मेदारी सीखता है कि उसके भरोसे कुछ जिंदगियां हैं। याद रखिए आज जो बच्चा चिड़िया का ख्याल रखेगा,कल वो बुजुर्गों,गरीबों, पर्यावरण का ख्याल रखेगा। एक बर्तन पानी,एक पूरी पीढ़ी के संस्कार बदल सकता है इसलिए बच्चों को इस पहल से जोड़ना बहुत आवश्यक है।

केवल घरों के भरोसे नहीं रहा जा सकता। नगर निगम हर पार्क में,बस स्टैंड पर,सरकारी भवनों की छत पर 'पक्षी जल केंद्र' बनाए। कॉर्पोरेट कल्चर में इसे शामिल करें। एक मिट्टी का बर्तन, हजारों की जान बचाएगा। इससे सस्ता परोपकार क्या होगा?

पक्षियों को पानी पिलाने के लिए न पैसा चाहिए, न समय। चाहिए बस थोड़ी सी नीयत। तो आज जब तपती दोपहर में आप एसी या कूलर की ठंडी हवा लें, तो एक मिनट बाहर निकलकर सोचिए कि इस 45 डिग्री की भीषण गर्मी में कोई पंख फड़फड़ा रहा है, उसकी चोंच सूख रही है,आंखें पानी तलाश रही हैं।

कुदरत ने हमें सक्षम बनाया है। पक्षियों के पास पंख हैं,पर पानी का इंतजाम नहीं। हमारे पास साधन हैं, पर फुर्सत नहीं। तो इस गर्मी एक वादा खुद से करें कि मेरी छत पर कोई परिंदा प्यासा नहीं रहेगा। मिट्टी के एक बर्तन और रोज का साफ पानी यह मेरी दिनचर्या का हिस्सा रहेगा। आज एक बर्तन जरूर रखिए। कल पक्षियों की चहचहाहट लौट आएगी क्योंकि जिंदगी बूंद-बूंद से ही बनती है फिर चाहे वह इंसान की हो या परिंदे की।

वह मेरी पनाह में इस तरह सिमट गई जैसे कोई क़श्ती तूफ़ान के बाद साहिल से आ लगी हो

डॉ. मुश्ताक़ अहमद शाह सहज़
हरदा मध्य

बरसों बीत गए थे,यादों की धूल ने उन रास्तों को धुंधला कर दिया था जिन पर हम कभी साथ चले थे। लेकिन जिंदगी के सफ़र में कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहाँ इंसान मुड़कर देखने पर मजबूर हो जाता है। एक रोज़ अचानक फ़ोन की घंटी बजी,और दूसरी तरफ़ से वह आवाज़ आई जिसे ज़माने की गर्द ने कहीं छुपा दिया था।

उसने कहीं से मेरा नंबर ढूँढा था। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी लरज़िश (कंपकंपाहट) थी। उसने कहा,मैं तन्हा हूँ। मैने पूछा कौन उसने फ़ौरन नाम बताया में पूछा गया,मुझे सब याद आने लगा,

उसकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि वक्त की बेरहमी ने उसे तोड़ कर रख दिया है। उसने बताया कि कैसे रफ़्ता-रफ़्ता सब उसे छोड़ते गए,कैसे रिश्तों की रौनकें मातम में बदल गईं। उसने कहा कि बरसों से मेरा ख़याल उसके ज़हन के किसी गोशे (कोने) में महफ़ूज़ था। आज जब उसके ज़ब्त की दीवार गिरी, तो उसने मुझे फ़ोन कर लिया।

शुरू में तो कोई रिश्ता साफ़ न था। उसने मुझे भाई कहकर पुकारा, शायद उस दर्द को कोई नाम देने की कोशिश की थी जिसे वह अकेले ढो रही थी। फ़ोन पर वह बहुत रोई। उसके आँसुओं में वह तमाम ज़हर बह गया जो बरसों से उसके सीने में जमा था। मेरी हमदर्दी और उसकी तन्हाई ने एक ऐसा पुल बनाया जिस पर हम फिर से मिलने लगे।

मुलाक़ातों का सिलसिला बढ़ा,तो परदे हटने लगे। एक दिन उसने अपनी आँखों में सिमटी सारी हक़ीक़त बयान कर दी। उसने कहा,मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ...या शायद मैं तो स्कूल के ज़माने से ही अपना दिल तुम्हें हार बैठी थी।

उसने बताया कि उस वक्त ज़ुबान हरकत न कर सकी,डर और हया ने लफ़्ज़ों को जकड़ लिया था। मैं हैरान था कि इस रिश्ते को क्या नाम दूँ? क्या यह महज़ हमदर्दी थी या बरसों पुरानी दबी हुई चिंगारी?

मगर जब मैंने उसकी आँखों में देखा, तो पाया कि मैं भी उसके लम्स (छूने) की तपिश से पिघलने लगा हूँ। उसकी आँखों के गहरे समंदर में मेरी तमाम दलीलें डूब चुकी थीं। रफ़्ता-रफ़्ता हम दोनों उस अफ़साने का हिस्सा बन गए जिसकी इब्तिदा (शुरुआत) तो बरसों पहले हुई थी, मगर तकमील (पूरा होना) अब मुक़द्दर थी।

शाम की सुर्ख़ लकीरें आसमान पर उभर आई थीं,जैसे किसी ने कोरे काग़ज़ पर मोहब्बत की इबारत लिख दी हो। हम दोनों शहर के उस ख़ामोश गोशे में बैठे थे जहाँ परिंदों की चहचहाहट के अलावा सिर्फ़ धड़कनों का शोर था।उसने अपनी मख़मली निगाहें उठाकर मुझे देखा, उन आँखों में अब आँसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी चमक थी जिसे मुद्दतों से लफ़्ज़ों की तलाश थी। उसने हौले से मेरा हाथ थाम लिया। उसके लम्स (स्पर्श) की तपिश ने मेरे वजूद में एक सहर (जादू) सा जगा दिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे बरसों की प्यासी ज़मीन पर बारिश की पहली बूंद गिरी हो।उसने आहिस्ता से कहा...अब और इंतज़ार नहीं होता। ये दूरियाँ,ये ख़ामोशियाँ अब मुझे काटने को दौड़ती हैं। उस पल मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैंने महसूस किया कि उसके सीने में धड़कता दिल और मेरी नब्ज़ की रफ़्तार एक ही लय में बह रहे हैं। वक्त ठहर गया था। न गुज़रे हुए कल का अंदेशा था,न आने वाले कल की फिक्र। बस वो थी,मैं था और दरमियान में फ़ैली हुई एक पाक रूहानी क़शिश।

मैंने उसे अपने क़रीब कर लिया। उसकी साँसों की गर्मी जब मेरी गर्दन से टकराई,तो लगा कि दुनिया की तमाम मुसाफ़िरतें (यात्राएं) ख़त्म हो गई हैं। वह मेरी पनाह में इस तरह सिमट गई जैसे कोई क़श्ती तूफ़ान के बाद साहिल से आ लगी हो। उस मक़ाम पर रूहें आपस में इस तरह पैवस्त (जुड़) हुईं कि यह पहचानना मुश्किल हो गया कि कहाँ उसकी हस्ती ख़त्म होती है और कहाँ से मेरा वजूद शुरू होता है।अब हम महज़ दो इंसान नहीं थे,बल्कि एक ऐसी मुकम्मल कहानी थे जिसे मंज़िल मिल चुकी थी। स्कूल के ज़माने का वो अनकहा इज़हार अब एक मुक़द्दस (पवित्र) हक़ीक़त बन चुका था। अंधेरा गहरा रहा था,मगर हमारे भीतर मोहब्बत का वो चिराग़ रौशन हो चुका था जिसे अब वक्त की कोई भी आँधी बुझा नहीं सकती थी।

जहां थे वहीं हैं ...

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर चार पर सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर कोई सिक्का गिरता, तो उसकी खनक से आधे शहर की नींद खुल जाती। पर यहाँ सिक्का नहीं, सिर्फ उम्मीदें गिर रही थीं–चुपचाप, बिना किसी शोर के।
प्लेटफॉर्म की उस उखड़ी हुई बेंच पर,जिसकी लकड़ी अब याददाश्त खो चुकी थी,तीन लोग बैठे थे। एक वह जो पिछले दस साल से सरकारी परीक्षा के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा था, दूसरा वह जो रिटायरमेंट के बाद अपनी रुकी हुई पेंशन की फ़ाइल ढूँढ रहा था, और तीसरा मैं, जो बस यह देखने आया था कि इंतज़ार आखिर दिखता कैसा है।
तभी एनाउंसमेंट हुआ, यात्री गण कृपया ध्यान दें! गाड़ी संख्या 420,अच्छे दिन एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से चौदह साल की देरी से चल रही है।
असुविधा के लिए हमें खेद नहीं है, क्योंकि हमें आदत है।

रिटायरमेंट वाले बाबूजी ने अपनी धुंधली ऐनक साफ़ की और बोले, बेटा,इस स्टेशन की सबसे बड़ी खूबी यही है। यहाँ ट्रेन आए न आए,घोषणाएँ बड़ी सुरीली होती हैं। सुनकर लगता है कि बस अगले ही पल सब ठीक हो जाएगा।
मैंने पूछा, तो आप घर क्यों नहीं जाते?
उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, घर जाकर क्या करूँगा? वहाँ बीवी पूछती है कि क्या लाए? यहाँ कम से कम यह भ्रम तो रहता है कि कुछ आने वाला है। भ्रम, बेटा,इस देश का सबसे बड़ा ऑक्सीजन सिलिंडर है।
तभी स्टेशन मास्टर की मेज पर पड़ा लाल झंडा हरे झंडे से फुसफुसाया, भाई, तू थक नहीं जाता? दिन भर लहराता रहता है, जैसे सच में कोई क्रांति आने वाली हो।
हरा झंडा थोड़ा और तनकर लहराया और बोला,मेरा काम क्रांति लाना नहीं,झुनझुना बजाना है। जब तक मैं हिलता रहूँगा, तब तक यह भीड़ शांत रहेगी। जिस दिन मैं स्थिर हो गया, उस दिन ये लोग इंजन ढूँढने लगेंगे। और इंजन तो कब का कबाड़ में बिक चुका है।
प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर एक चाय वाला कोयले की राख से अपना हाथ पोंछ रहा था। उसकी केतली खाली थी,पर आग जल रही थी। मैंने पास जाकर पूछा, चाय मिलेगी?
उसने बिना ऊपर देखे कहा, चाय तो खत्म हो गई साहब, बस भाप बची है। पीनी है तो बताइए, आजकल शहर में भाप की ही सबसे ज्यादा मांग है। कोई आश्वासन की भाप पी रहा है,कोई विकास की।
अचानक दूर से एक लाइट चमकी। भीड़ में थोड़ी हलचल हुई। लोग अपने झोले उठाकर खड़े हो गए। धूल उड़ी, शोर बढ़ा, और एक बहुत बड़ा लोहे का ढांचा तेज़ी से प्लेटफॉर्म को चीरता हुआ निकल गया। वह ट्रेन नहीं थी, सिर्फ एक खाली मालगाड़ी थी जिस पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था–कल ने कल से कहा तुम्हारा कल, कल की तरह होगा।
भीड़ फिर से बेंचों पर बैठ गई। धूल जम गई।
पेंशन वाले बाबूजी ने अपनी लाठी उठाई और चलने लगे। मैंने पूछा, अब कहाँ?
उन्होंने जवाब दिया, अगले स्टेशन। सुना है वहाँ की घोषणाएँ और भी मधुर हैं। कम से कम मरते दम तक संगीत तो अच्छा मिलता रहे।
मैं वहीं खड़ा रहा। स्टेशन की घड़ी की सुइयाँ अब भी वहीं थीं जहाँ मैं आया था। ऐसा लगा मानो समय चल नहीं रहा, बस अपनी जगह पर कदमताल कर रहा है ताकि हमें लगे कि हम कहीं पहुँच रहे हैं।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

वाहन खरीदी में जबरन बीमा और एक्सेसरी पर सख्ती

आदेश के बाद भी जमीनी हकीकत पर सवाल

राहत का आदेश...लेकिन भरोसा अभी अधूरा

- वाहन खरीदी में जबरन बीमा पर सख्ती, परिवहन विभाग का बड़ा आदेश
- 'शोरूम से ही बीमा कराओ' दबाव खत्म ? आदेश के बाद भी उठे सवाल
- वाहन खरीदारों को राहत,अब बीमा और एक्सेसरी आपकी पसंद से
- जबरन बीमा और कैशलेस के नाम पर दबाव पर प्रशासन सख्त
- डीलरों की मनमानी पर रोक,बीमा कहीं से भी कराने की आजादी
- वाहन खरीद में 'पैकेज सिस्टम' पर ब्रेक,उपभोक्ताओं को मिली राहत
- बीमा के नाम पर डराना-धमकाना अब नहीं चलेगाः परिवहन विभाग
- कैशलेस सुविधा के नाम पर खेल बंद ? नए आदेश से मचा हलचल
- वाहन खरीदी में उपभोक्ता अधिकार मजबूत, जबरन बीमा पर रोक
- शोरूम की शर्तों से आजादी, बीमा और एक्सेसरी अब वैकल्पिक

-संवाददाता-
अंबिकापुर/रायपुर,28 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ में वाहन खरीदी के दौरान लंबे समय से चली आ रही एक बड़ी समस्या शोरूम द्वारा बीमा और एक्सेसरी जबरन थोपने पर आखिरकार प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है, परिवहन आयुक्त द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि किसी भी ग्राहक पर बीमा या अतिरिक्त सामान खरीदने का दबाव नहीं बनाया जा सकता, यह आदेश उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर जरूर है,लेकिन वर्षों से चले आ रहे व्यवहार और जमीनी अनुभव को देखते हुए यह सवाल भी उतना ही बड़ा है कि क्या यह निर्देश वास्तव में लागू हो पाएगा।

मामले की पृष्ठभूमि है की वाहन खरीदी में 'पैकेज' की मजबूरी

छत्तीसगढ़ सहित कई हिस्सों में वाहन खरीदना केवल गाड़ी लेने भर का मामला नहीं रह गया था, ग्राहक जब शोरूम में जाते थे, तो उन्हें एक 'पैकेज' दिया जाता था, जिसमें गाड़ी के साथ बीमा, एक्सेसरी और कई अन्य सेवाएं जोड़ दी जाती थीं, ग्राहकों के पास विकल्प होते हुए भी उन्हें यह महसूस कराया जाता था कि यह सब अनिवार्य है, खासकर बीमा के मामले में यह दबाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता था।

शोरूम में ग्राहकों को झेलनी पड़ती थी सबसे ज्यादा परेशानी

वाहन खरीदी के समय ग्राहकों को सबसे ज्यादा दिक्कत शोरूम में ही होती थी, वाहन पसंद करने और कीमत तय होने के बाद असली चुनौती शुरू होती थी बीमा और एक्सेसरी के चयन की,अक्सर शोरूम के कर्मचारी ग्राहकों से सीधे कहते थे कि बीमा उन्हें वहीं से कराना होगा, यदि ग्राहक बाहर से बीमा कराने की बात करते,तो उन्हें हतोत्साहित किया जाता था,इस स्थिति में ग्राहक खुद को असहाय महसूस करते थे,क्योंकि गाड़ी की डिलीवरी भी कई बार बीमा से जोड़ दी जाती थी।

डर और दबाव का माहौलः 'यहां से नहीं कराओगे तो नुकसान होगा'-

ग्राहकों के अनुसार उन्हें कई तरह के डर दिखाए जाते थे, जैसे अगर बाहर से बीमा कराओगे तो क्लेम नहीं मिलेगा, कैशलेस सुविधा बंद हो जाएगी, कंपनी सहयोग नहीं करेगी, इन बातों से ग्राहक मानसिक रूप से दबाव में आ जाते थे और अंततः शोरूम के माध्यम से ही बीमा लेने के लिए मजबूर हो जाते थे, भले ही वह महंगा क्यों न हो।

हर वर्ग के वाहन खरीदार हुए प्रभावित-

यह समस्या केवल कार खरीदारों तक सीमित नहीं थी, दोपहिया वाहन लेने वाले युवा, परिवार के लिए कार खरीदने वाले उपभोक्ता, व्यवसाय के लिए कमर्शियल वाहन लेने वाले लोग, कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर खरीदने वाले किसान, सभी इस दबाव का सामना करते रहे, खासकर कमर्शियल और ट्रैक्टर श्रेणी में बीमा राशि अधिक होने के कारण ग्राहकों पर आर्थिक बोझ भी काफी बढ़ जाता था।

बीमा की ऊंची लागत और विकल्प की कमी-

शोरूम के माध्यम से कराए जाने वाले बीमा की कीमत अक्सर बाजार दर से अधिक होती थी, ग्राहक यदि खुद बीमा कंपनियों या ऑनलाइन माध्यम से तुलना करते, तो उन्हें कम कीमत में बेहतर विकल्प मिल सकते थे, लेकिन जानकारी के अभाव और शोरूम के दबाव के कारण अधिकांश लोग ऐसा नहीं कर पाते थे और अधिक कीमत चुकाने को मजबूर हो जाते थे।

रिन्यूअल के समय भी जारी रहता था दबाव

समस्या केवल वाहन खरीद तक सीमित नहीं थी, बीमा के रिन्यूअल के समय भी ग्राहकों को इसी तरह के दबाव का सामना करना पड़ता था, उन्हें फिर से यह कहा जाता था कि यदि बीमा बाहर से कराया गया,तो भविष्य में क्लेम नहीं मिलेगा या कैशलेस सुविधा नहीं दी जाएगी, इस कारण कई ग्राहक हर साल उसी शोरूम या एजेंसी से बीमा कराने को मजबूर रहते थे।

कैशलेस सुविधाः सबसे बड़ा हथियार

शोरूम और डीलरों द्वारा ग्राहकों पर दबाव बनाने का सबसे बड़ा माध्यम 'कैशलेस सुविधा' थी, ग्राहकों को यह बताया जाता था कि केवल शोरूम से कराए गए बीमा पर ही कैशलेस सुविधा मिलेगी, जबकि बाहर से कराए गए बीमा पर उन्हें यह सुविधा नहीं दी जाएगी,हालांकि नियमों के अनुसार, यदि बीमा कंपनी और सर्विस सेंटर के बीच टाई-अप है,तो कैशलेस सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे बीमा कहीं से भी कराया गया हो।

परिवहन आयुक्त का आदेश : क्या कहा गया है...

17 अप्रैल 2026 को जारी आदेश में परिवहन आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि बीमा किसी भी कंपनी से कराया जा सकता है,डीलर किसी विशेष बीमा के लिए बाध्य नहीं कर सकते,एक्सेसरी पूरी तरह वैकल्पिक हैं,जबरदस्ती करना अनुचित व्यापार व्यवहार है इसके साथ ही सभी पंजीयन प्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र के डीलरों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करें।

कानूनी आधार : उपभोक्ता के अधिकार सुरक्षित

आदेश में मोटर वाहन अधिनियम,1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और IRDAI के दिशा-निर्देशों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया है कि बीमा अनिवार्य है,लेकिन स्त्रोत चुनना ग्राहक का अधिकार है, एक्सेसरी वैकल्पिक हैं किसी भी प्रकार का 'टाई-इन अरेंजमेंट' अवैध है यह प्रावधान उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।

शिकायत पर कार्रवाई का प्रावधान

यदि किसी डीलर द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके खिलाफ केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत कार्रवाई की जाएगी, इसमें लाइसेंस पर प्रभाव डालने जैसी कड़ी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है,जिससे डीलरों के लिए यह चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।

सरगुजा संभाग की स्थितिः अलग तरह की विसंगति-सरगुजा संभाग में एक अलग प्रकार की स्थिति सामने आई है, यहां अधिकांश शोरूम सूरजपुर जिले में संचालित होते हैं,लेकिन उनके ट्रेड सर्टिफिकेट अंबिकापुर के नाम से जारी हैं, यह व्यवस्था नियमों के अनुरूप नहीं मानी जा रही और इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, हालांकि यहां दबाव के मामले अपेक्षाकृत कम बताए जाते हैं,लेकिन पारदर्शिता की कमी साफ नजर आती है।

क्या आदेश से बदलेगी स्थिति?- यह आदेश निश्चित रूप से सकारात्मक पहल है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे जमीनी स्तर पर कितनी गंभीरता से लागू किया जाता है, यदि निगरानी मजबूत नहीं हुई और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई,तो यह आदेश केवल कागजों तक सीमित रह सकता है।

उपभोक्ताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण

इस पूरे मामले में उपभोक्ताओं की जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है, उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, दबाव पड़ने पर शिकायत करनी चाहिए, और विकल्पों की तुलना कर निर्णय लेना चाहिए,जब तक ग्राहक खुद सजग नहीं होंगे,तब तक इस तरह की प्रथाओं पर पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल होगा।

सही दिशा में कदम, लेकिन लंबा सफर बाकी

वाहन खरीदी के दौरान बीमा और एक्सेसरी को लेकर वर्षों से चली आ रही समस्याओं पर यह आदेश एक महत्वपूर्ण कदम है, इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद जरूर है, लेकिन असली परीक्षा इसके क्रियान्वयन की होगी, अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस पर कितनी सख्ती से अमल कराता है और क्या वास्तव में वाहन खरीदारों को बिना दबाव के निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिल पाती है या नहीं।

ईमानदारी की मिसाल : युवक ने सड़क पर मिले 13 हजार रुपए थाने में किए जमा

स्कूटी सवार की जेब से गिरते देखे थे नोट, बिना देर किए पुलिस को सौंपे रुपए

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,28 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

जहां एक ओर लोग छोटी-छोटी बातों में भी लालच दिखाने से नहीं चूकते, वहीं कुछ लोग अपनी ईमानदारी से समाज के लिए मिसाल पेश करते हैं। ऐसा ही एक मामला शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां एक युवक ने सड़क पर मिले 13 हजार रुपए पुलिस के हवाले कर दिए। जानकारी के अनुसार, गांधीनगर सब्जी मार्केट के पास एक युवक को सड़क पर 500-500 रुपए के नोट पड़े मिले। युवक ने नोट उठाकर गिने तो कुल 13 हजार रुपए निकले। खास बात यह रही कि युवक ने इन रुपयों को अपने पास रखने के बजाय सीधे थाने पहुंचकर जमा कर दिया। युवक ने पुलिस को बताया कि उसने इन रुपयों को एक स्कूटी सवार की जेब से गिरते हुए देखा था। स्कूटी सवार पीले रंग की शर्ट पहने हुए था और गांधीनगर बैरियर की ओर से हनुमान मंदिर की दिशा में जा रहा था। मौके पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए युवक ने तुरंत रुपए उठाए और सुरक्षित रखने के लिए थाने पहुंच गया।

किराए के मकान में रहता है युवक

रुपए जमा करने वाले युवक का नाम मनोज कुमार सिंह (22) है। वह सूरजपुर जिले के ओडगी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इंद्रपुर, कुदरगढ़ का निवासी है। वर्तमान में वह गांधीनगर के मुक्तिपारा में किराए के मकान में रहता है। उसने बताया कि वह दोपहर में बस से उतरकर अपने घर जा रहा था, तभी उसे सड़क पर ये रुपए दिखाई दिए।

पुलिस ने की सराहना

युवक की ईमानदारी से प्रभावित होकर गांधीनगर पुलिस ने उसकी सराहना की है। पुलिस ने रुपए अपने पास सुरक्षित रख लिए हैं और असली मालिक की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जिसके भी ये रुपए हैं,वह थाने आकर पहचान के आधार पर उन्हें प्राप्त कर सकता है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि आज भी समाज में ईमानदारी जिंदा है और ऐसे लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं।

तालाबों पर कब्जे के खिलाफ सख्ती...भातूपारा से शुरू हुआ अभियान

निगम-प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई,सौंदर्यीकरण और सीमांकन से अतिक्रमण रोकने की तैयारी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,28 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

शहर के तालाबों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। भू-माफियाओं द्वारा जल स्त्रोतों को पाटकर कब्जा करने की शिकायतों के बीच नगर निगम और प्रशासन ने संयुक्त अभियान शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत मंगलवार को भातूपारा स्थित पुराने तालाब से की गई, जहां अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर बाउंड्रीवाल ध्वस्त कर दी गई। जानकारी के अनुसार, रिंग रोड से लगे भातूपारा तालाब के पीछे होटल पर्पल आर्किड के संचालक ने बड़े हिस्से में मिट्टी भरकर कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, तालाब के प्राकृतिक जल निकासी मार्ग को भी बंद कर दिया गया था,जिससे पानी का प्रवाह बाधित हो रहा था और आसपास के लोगों को परेशानी हो रही थी। इस मामले को लेकर वार्डवासियों और कांग्रेस पार्षद शुभम जायसवाल ने निगम आयुक्त से शिकायत की थी। निगम आयुक्त डीएन कश्यप ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संचालक मुकेश अग्रवाल को नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर मंगलवार सुबह निगम और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। चार जेसीबी और डंपर की मदद से तालाब में डाली गई मिट्टी हटाई गई और अवैध बाउंड्रीवाल को तोड़ दिया गया। निगम आयुक्त ने बताया कि तालाब की जमीन का सीमांकन राजस्व अमले द्वारा किया जाएगा। सीमांकन के बाद शेष बचे अतिक्रमणों को भी हटाने की कार्रवाई तेज की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि तालाब के प्राकृतिक नाले को पाटना गंभीर लापरवाही है, जिसे जल्द बहाल किया जाएगा, ताकि जल निकासी की व्यवस्था फिर से सुचारू हो सके। भाजपा पार्षद आलोक दुबे के मुताबिक,राजस्व रिकॉर्ड में भातूपारा तालाब का रकबा 11 एकड़ 81 डिसमिल दर्ज है, लेकिन अतिक्रमण के चलते अब यह दो एकड़ से भी कम रह गया है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो शहर के अन्य तालाब भी खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। ऐसे में सभी तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कर संरक्षित करना जरूरी है।

सौंदर्यीकरण से रोका जाएगा कब्जा

कलेक्टर अजीत वसंत ने हाल ही में हुई बैठक में तालाबों पर अतिक्रमण रोकने के लिए ठोस योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नगरीय क्षेत्रों में स्थित तालाबों का चिन्हांकन कर उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इससे न केवल तालाबों की उपयोगिता बढ़ेगी, बल्कि अतिक्रमण पर भी रोक लगेगी। इसके लिए नगर निगम और राजस्व विभाग को संयुक्त रूप से कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा गया है।

शहरभर में चलेगा अभियान

निगम आयुक्त डीएन कश्यप ने बताया कि यह कार्रवाई केवल भातूपारा तक सीमित नहीं रहेगी। शहर के सभी तालाबों का सर्वे कर अतिक्रमण की पहचान की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से उन्हें हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल स्त्रोतों को बचाना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि अब तालाबों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा। आने वाले दिनों में शहर के अन्य तालाबों पर भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है।

सही दवा,शुद्ध आहार' अभियान शुरू, बाजार में दवाओं व कॉस्मेटिक की जांच तेज

15 दिन तक चलेगा सघन अभियान,बिना बिल बिक्री पर सख्ती,नमूने जांच के लिए भेजे गए...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,28 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

जिले में आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाएं व खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सही दवा, शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ़ का आधार अभियान की शुरुआत कर दी गई है। कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा 27 अप्रैल से 11 मई तक 15 दिवसीय सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पहले चरण में शहरी क्षेत्रों में कॉस्मेटिक उत्पादों के थोक विक्रेताओं,होलसेलर्स और मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कई जगहों पर कॉस्मेटिक उत्पाद बिना बिल के बेचे जाते पाए गए, जिस पर विभाग ने सख्ती दिखाई है।

बिल और गुणवत्ता की जांच पर जोर : निरीक्षण के दौरान पैक्ड और खुले उत्पादों के बिलों की बारीकी से जांच की गई। साथ ही हेयर डाई, नेल पॉलिश, क्रीम, लिक्विड, गंधक उत्पाद और मिनरल ऑयल जैसे सामानों की गुणवत्ता भी परखी गई। संदिग्ध पाए गए उत्पादों के नमूने लेकर प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान दवा दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों की भी जांच की जाएगी, ताकि नकली या घटिया उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।

दवाओं की उपलब्धता पर भी उठे सवाल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,28 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा औषधि विक्रेता संघ ने जिले में दवाओं की सीमित उपलब्धता और कुछ कंपनियों के मोनोपॉली सिस्टम को लेकर चिंता जताई है। संघ का कहना है कि कई जरूरी दवाएं केवल अस्पतालों की फार्मेसी तक सीमित रह जाती हैं, जिससे आम लोगों को समय पर दवाएं नहीं मिल पातीं। इस संबंध में संघ के पदाधिकारियों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) अंबिकापुर इकाई के पदाधिकारियों से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने रिटेल केमिस्ट की समस्याओं और इससे जुड़े जन स्वास्थ्य के मुद्दों को विस्तार से रखा। संघ के अध्यक्ष अमित अग्रवाल और अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि उनका उद्देश्य जरूरी दवाओं की उपलब्धता सभी केमिस्ट तक सुनिश्चित करना है, ताकि मरीजों को समय पर उपचार मिल सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन और संबंधित संस्थाओं के सहयोग से इस दिशा में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अनुसार यह अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा। दवाओं और खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उनकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

CMYK

चेक डैम जांच टीम पर उठे सवाल : गुणवत्ता जांच हुई या मीडिया मैनेजमेंट?

मनरेगा कार्य में अनियमितता की शिकायत के बाद बनी थी जिला और प्रदेश स्तरीय जांच टीम,उपलब्धि वाली खबरों से बढ़ी चर्चा

-सुदामा राजवाड़े-

राजपुर/बलरामपुर,28 अप्रैल 2026। जिले के समरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राजपुर जनपद क्षेत्र में मनरेगा के तहत बनाए गए चेक डैमों की गुणवत्ता और मजदूरी भुगतान को लेकर उठे सवाल अब जांच टीमों पर भी खड़े होने लगे हैं। ग्रामीणों की शिकायत और मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद जिला व प्रदेश स्तर पर जांच टीम गठित की गई थी,लेकिन अब उपलब्धियों से जुड़ी खबरों के प्रकाशन के बाद जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।

मार्च में जारी हुआ था जांच आदेश

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग बलरामपुर-रामानुजगंज के कार्यपालन अभियंता द्वारा 12 मार्च 2026 को पत्र क्रमांक 258 जारी कर राजपुर जनपद क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों में मनरेगा से बने चेक डैमों की गुणवत्ता जांच के आदेश दिए गए थे। जांच के दायरे में चंद्रगढ़, सिंचोरा, लडुआ, पतरापारा, चिलमा, बड़ी चलगली, कोडू, बदौली, कारवां, पकराड़ी, डीगनगर, कुंदी खुर्द, पहाड़खडूवा, खोखनिया समेत कई गांव शामिल थे।

जिला स्तर पर बनाई गई थी टीम : जिला स्तर पर गठित टीम में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अनुविभागीय अधिकारी सुदर्शन उरांव को अध्यक्ष बनाया गया था। साथ ही कुसमी के अनुविभागीय अधिकारी बसिल मिंज,उप अभियंता तनुज अंबष्ट और राजपुर के उप अभियंता राजेंद्र दुबे को सदस्य बनाया गया था। इधर,प्रदेश स्तर से भी अलग जांच टीम गठित किए जाने की जानकारी सामने आई थी।

उपलब्धि वाली खबरों से बढ़े सवाल : मामले में चर्चा तब और तेज हो गई, जब चंद्रगढ़ के बरौना नाला में बने चेक डैम को किसानों के लिए लाभकारी बताते हुए कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्धि संबंधी खबरें प्रकाशित हुईं। खबरों में दावा किया गया कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा और लाभार्थियों के नाम भी प्रकाशित किए गए। अब सवाल उठ रहे हैं कि जब जांच प्रक्रिया जारी थी, तब उपलब्धियों का प्रचार किस आधार पर किया गया? क्या जांच पूरी हो चुकी थी या फिर विभागीय छवि सुधारने के लिए यह प्रयास किया गया?

पहले मशीन से काम कराने के आरोप लगे थे : स्थानीय ग्रामीणों और पहले प्रकाशित खबरों में आरोप लगाए गए थे कि मनरेगा कार्य में मजदूरों की जगह मशीनों का उपयोग किया गया। साथ ही निर्माण गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर अनियमितताओं की शिकायत की गई थी।

अधिकारियों से संपर्क नहीं हो सका...

मामले की वास्तविक स्थिति जानने के लिए जांच टीम अध्यक्ष सुदर्शन उरांव तथा कार्यपालन अभियंता सच्चिदानंद कांत से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ।

अब प्रशासन से जवाब की अपेक्षा

जिले में चर्चा है कि क्या प्रशासन बरौना नाला में बने चेक डैम की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट है? और यदि जांच पूरी हो चुकी है तो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? ग्रामीणों और आमजन की नजर अब जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों के अगले कदम पर टिकी है।

साइबर सुरक्षा पर पुलिस अफसर-कर्मचारियों को प्रशिक्षण : एक दिवसीय कार्यशाला में सिखाए बचाव के तरीके

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,28 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरगुजा पुलिस ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक दिवसीय साइबर हाईजीन एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। इसमें जिले के थाना-चौकी प्रभारियों, कार्यालयीन अधिकारियों-कर्मचारियों और सीसीटीएनएस कार्य से जुड़े स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला का आयोजन डीआईजी एवं एसएसपी राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में किया गया। पुलिस मुख्यालय रायपुर की टेक्निकल ब्रांच से आए साइबर कमांडो ने प्रशिक्षण दिया।

डेटा सुरक्षा और साइबर अटैक से बचाव की जानकारी

प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों-कर्मचारियों को बताया गया कि साइबर हाईजीन अपनाकर डेटा चोरी, साइबर अटैक और अन्य ऑनलाइन खतरों से बचा जा सकता है। सिस्टम और डिवाइस को सुरक्षित रखने के लिए नियमित सावधानियां जरूरी हैं।

ये 10 जरूरी बातें बताई गईं...

- हर अकाउंट के लिए अलग और मजबूत पासवर्ड रखें।
- ईमेल और बैंक खातों में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करें।
- मोबाइल,कंप्यूटर और ऐप्स को समय-समय पर अपडेट करें।
- संदिग्ध लिंक, ईमेल और मैसेज पर क्लिक न करें।
- जरूरी फाइलों का नियमित बैकअप लें।
- सार्वजनिक Wi-Fi पर बैंकिंग या संवेदनशील काम न करें।
- विश्वसनीय एंटीवायरस इंस्टॉल करें।
- मोबाइल ऐप्स को सीमित अनुमति दें।
- सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा करने से बचें।
- सार्वजनिक कंप्यूटर पर काम के बाद लॉगआउट जरूर करें।
- नेटवर्क और हार्डवेयर की जांच भी हुई।

साइबर कमांडो टीम ने पुलिस विभाग के हार्डवेयर, नेटवर्क और अन्य तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर की साइबर सुरक्षा के नजरिए से जांच भी की। कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लों, डीएसपी सुरेश भगत, टेक्निकल ब्रांच से साइबर कमांडो दिलीप सिंह और रिखम साहू सहित जिले के पुलिस अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

900 सीढ़ियां चढ़ते ही थमी सांस,प्रसिद्ध कुदरगढ़ धाम में श्रद्धालु की मौत

-संवाददाता-

सूरजपुर,28 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले स्थित प्रसिद्ध कुदरगढ़ देवी धाम में दर्शन करने पहुंचे एक श्रद्धालु की अचानक मौत हो गई। भीषण गर्मी के बीच करीब 900 सीढ़ियां चढ़ने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान कोरिया जिले के निवासी फूल सिंह के रूप में हुई है। वे अपने परिवार के साथ मां बागेश्वरी देवी के दर्शन के लिए कुदरगढ़ धाम पहुंचे थे। परिजनों के अनुसार यात्रा के दौरान सब कुछ सामान्य था, लेकिन मंदिर पहुंचने से पहले अचानक तबीयत बिगड़ गई। बताया गया कि फूल सिंह 900 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर जा रहे थे। रास्ते में एक स्थान पर वे पीछे आ रहे परिजनों का इंतजार करने के लिए रुके थे। इसी दौरान अचानक चक्कर आने के बाद वे बेहोश होकर गिर पड़े।

धनलक्ष्मी स्कीम में ज्यादा लाभ का झांसा देकर 5.72 लाख की ठगी: आरोपी रायपुर से गिरफ्तार

गांधीनगर पुलिस की कार्रवाई; निवेश के नाम पर खाते में रकम डलवाई, मोबाइल और सिम जब्त

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,28 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में निवेश पर अतिरिक्त लाभ दिलाने का झांसा देकर 5 लाख 72 हजार रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ग्राहकों को धनलक्ष्मी स्कीम में ज्यादा फायदा दिलाने का भरोसा देकर रकम अपने खातों में जमा कराता था। पुलिस के मुताबिक, प्रार्थी अविनाश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह कल्याण ज्वेलर्स की स्वर्ण योजना से जुड़ा था। इसी दौरान शो-रूम कर्मचारी राजेश कुमार तिवारी और अन्य लोगों ने

उसे अतिरिक्त लाभ वाली स्कीम बताई। शुरुआत में 30 हजार रुपए जमा करवाकर 10 दिन बाद 40 हजार रुपए लौटाए गए, जिससे प्रार्थी का भरोसा जीत लिया गया। इसके बाद नवंबर से दिसंबर 2025 के बीच आरोपी ने अलग-अलग क्यूआर कोड भेजकर निवेश के नाम पर 7 लाख 59 हजार रुपए जमा करवाए। बाद में केवल 1 लाख 87 हजार रुपए लौटाए गए। इस तरह कुल 5 लाख 72 हजार रुपए की ठगी हुई।

व्हाट्सएप चैट और ट्रांजेक्शन डिटेल से खुलासा : मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल और व्हाट्सएप चैटिंग के प्रिंट जब्त किए। जांच में आरोपी राजेश कुमार तिवारी की संलिप्तता सामने आने पर पुलिस टीम ने उसे रायपुर से पकड़ लिया। आरोपी की पहचान राजेश कुमार तिवारी (28), निवासी तेंदुपारा राधापुर वार्ड-03, प्रतापगढ़, थाना सीतापुर, जिला सरगुजा के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने ठगी करना स्वीकार किया।

मोबाइल-सिम जब्त,अन्य आरोपी फरार : पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त वन प्लस कंपनी का मोबाइल और सिम कार्ड जब्त किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

एसएसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई : डीआईजी एवं एसएसपी राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देश पर थाना गांधीनगर पुलिस ने कार्रवाई की। पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी प्रवीण कुमार द्विवेदी सहित पुलिस टीम सक्रिय रही।

बहुउद्देशीय स्कूल में एसएमडीसी बैठक संपन्न नए सत्र की तैयारियों पर बनी रणनीति

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,28 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अंबिकापुर में सोमवार को स्कूल प्रबंधन एवं विकास समिति (एसएमडीसी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 की तैयारियों और विद्यालय के समग्र विकास को लेकर चर्चा की गई। बैठक में समिति अध्यक्ष अभिमन्यु गुप्ता, सदस्य विकास पांडेय, रूपेश दुबे, संजीव वर्मा, सुश्री बबली नेताम तथा प्राचार्य एडवर्ड टोप्पो विशेष रूप से मौजूद रहे।

प्राचार्य के प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकृति : प्राचार्य एडवर्ड टोप्पो और उप-प्राचार्य शैलेंद्र सिंह सेंगर द्वारा विद्यालय विकास, शैक्षणिक सुधार और नए सत्र की तैयारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। समिति ने सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकृत कर दिया। इन्हें आगामी सत्र से लागू किया जाएगा।

खेल सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर

एसएमडीसी सदस्य एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष तथा पार्षद विकास पांडेय ने विद्यालय में खेल गतिविधियों के विस्तार और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए विशेष योजना तैयार करने की बात कही।

थोड़ी सी सावधानी और डिजिटल हाइजीन अपनाकर बचे जा सकते हैं बड़े नुकसान से

इंजीनियरिंग कॉलेज में व्याख्यान,रैनसमवेयर व डिजिटल फ्रॉड से बचाव के बताए उपाय

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,28 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। बढ़ते साइबर अपराधों के बीच लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में साइबर सुरक्षा पर व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने कहा कि डिजिटल दौर में सुरक्षा केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी भी है। महाविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में चितकारा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ के प्रो-वाइस चांसलर डॉ. पी.के. खोसला शामिल हुए। उन्होंने 'साइबर सुरक्षाः एक साझा जिम्मेदारी' विषय पर विस्तार से जानकारी दी। डॉ. खोसला ने अपने व्याख्यान में वर्तमान समय में बढ़ रहे साइबर अपराधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने रैनसमवेयर अटैक, डिजिटल अरेस्ट जैसे नए खतरों के बारे में बताया और उनसे बचाव के उपाय समझाए। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी सावधानी और डिजिटल हाइजीन अपनाकर बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। व्याख्यान में व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर डेटा सुरक्षा को मजबूत करने की बात कही गई। उन्होंने पासवर्ड सुरक्षा, संदिग्ध लिंक से बचाव और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार को जरूरी बताया।

छात्र-छात्राओं ने लिया लाभ

कार्यक्रम में महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के प्राध्यापक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। सभी ने व्याख्यान को उपयोगी बताते हुए इससे नई जानकारी मिलने की बात कही। कार्यक्रम के संयोजक डॉ. केतन चौरसिया और डॉ. मोहन राव मामीडकर रहे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. राम नारायण खरे ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से छात्रों में जागरूकता बढ़ती है और उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा सकता है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध पर मंडल महिला मोर्चा का जन आक्रोश

घड़ी चौक में रैली और पुतला दहन,महिलाओं के अधिकारों पर समझौता नहीं करने का ऐलान

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,28 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर घड़ी चौक में मंडल महिला मोर्चा द्वारा 'जन आक्रोश रैली' का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। रैली के बाद पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया गया।

महिला नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन : रैली का नेतृत्व भाजपा सरगुजा अंतर्गत महिला मोर्चा महामाया मंडल अध्यक्ष सरस्वती यादव एवं समलाया मंडल अध्यक्ष शालिनी सिंह ने किया। दोनों नेताओं के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

महिलाओं के सम्मान पर हमला बताया : महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सम्मान, अधिकार और सशक्तिकरण से जुड़ा विषय है। इसका विरोध महिलाओं की प्रगति और भागीदारी के खिलाफ कदम है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा : कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है। महिला मोर्चा इस मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाएगा और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करेगा।

कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे उपस्थित : इस अवसर पर जिला महामंत्री विनोद हर्ष, विकास पांडेय, काशीनाथ तिवारी, वैभव सिंह देव, शुभांगी बिहाड़े, मनोज कंसारी, प्रियंका चौबे, नीलू गुप्ता, प्रिया सिंह, दीक्षा अग्रवाल, अभिषेक सिंह देव, किरण सिंह तोमर, बबली नेताम, सीमा कश्यप, संगीता सोनी, गीता पांडे, प्रभा यादव, अर्चना वर्मा, रीना राय, पूर्णिमा सोनी, रीना भारती, नेहा सोनवानी, राखी यादव, सत्यम सिंह, अनुज सिंह, धनंजय द्विवेदी, विकास सोनी, सुमित यादव, शुभम भदोरिया, सुधांशु चौबे सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

गांजा तस्करी कार्रवाई के दौरान पुलिस की बोलेरो लेकर फरार हुआ आरोपी गिरफ्तार

मोबाइल लोकेशन से वाहन बरामद,सर्चिंग के बाद आरोपी भी पकड़ाया

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,28 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में गांजा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक आरोपी पुलिस की बोलेरो वाहन लेकर फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मोबाइल लोकेशन की मदद से वाहन बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

सत्तीपारा क्षेत्र में गांजा बिक्री की मिली थी सूचना : जानकारी के अनुसार, कोतवाली थाना पुलिस को सत्तीपारा क्षेत्र में गांजा की अवैध बिक्री और तस्करी की सूचना मिली थी। सूचना पर प्रशिक्षु डीएसपी निशांत कुर्रे के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की।

लापरवाही का फायदा उठाकर लेकर भागा वाहन : पुलिस टीम जांच के लिए आसपास तलाशी में जुटी थी। इसी दौरान बोलेरो वाहन की चाबी गाड़ी में ही लगी रह गई। मौके का फायदा उठाकर शातिर आरोपी मुकेश नामदेव ने पहले पास के मकान की छत पर चढ़कर स्थिति

देखी, फिर नीचे कूदकर सीधे पुलिस बोलेरो में बैठ गया और वाहन लेकर फरार हो गया।

वाहन गायब देख पुलिस रह गई दंग : जब पुलिस टीम वापस वाहन के पास पहुंची तो बोलेरो गायब देखकर सभी हैरान रह गए। कुछ समय के लिए मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। बताया गया कि प्रशिक्षु डीएसपी का मोबाइल फोन भी वाहन में ही छूट गया था।

मोबाइल लोकेशन से पकड़ा गया आरोपी : इसके बाद पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर लोकेशन ट्रेस की और तकनीकी सहायता से वाहन का पता लगाया। पीछा करते हुए पुलिस टीम ने राम मंदिर के पास से बोलेरो वाहन सुरक्षित बरामद कर लिया।

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा,छ0ग0

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक हितेश श्रीवास्तव हरिश श्रीवास्तव निवासी केदारपुर थाना गांधीनगर तहसील अम्बिकापुर ने कराया है कि आवेदक के (माता) स्व. सुषमा श्रीवास्तव आ0. श्री हरिश श्रीवास्तव की दिनांक 08/11/2020 को स्थान निवास में मृत्यु हुई है।

आवेदक के मृत्यु उपरांत मृत्यु का पंजीयक नहीं कराया गया है। अतः प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने पर यह आवेदन पेश किया गया है।

उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन से 15 दिवस तक न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 28/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी।

(सील) तहसीलदार
अम्बिकापुर,सरगुजा

नाम परिवर्तन सूचना

मैं गोपाल सिंह आ. पुन्नी राम, आयु- 50 वर्ष, जाति कंवर, निवासी ग्राम भालूकछार, पोस्ट बरगवां, थाना व तहसील दरिमा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी हूँ । जो कि मेरे पुत्री कुमारी मलिका सिंह (Malika Singh) है जिसका आधार कार्ड नं0 3166 1999 5677 है जिसमें उसका नाम मनिका अंकित हो गया है जो गलत है । कि, मैं अपने पुत्री के आधार कार्ड के अलावा अन्य शैक्षणिक 14 प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों में नाम कुमारी मलिका सिंह अंकित है, जो सत्य एवं सही है। अतः कुमारी मलिका सिंह को सभी शासकीय एवं अर्धशासकीय सभी दस्तावेज में पढ़ा एवं लिखा जावे। जो कि पुत्री के आधार कार्ड में अंकित गलत नाम मनिका के स्थान पर कुमारी मलिका सिंह अंकित कराये जानो बावत स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

सपथकर्ता
गोपाल सिंह
ग्राम भालूकछार,पोस्ट बरगवां,
थाना व तहसील दरिमा
जिला सरगुजा छत्तीसगढ

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगांव,तहसील-भटगांव

रा0प्र0क्र0 /ब-121/2017-18

ईश्तहार

आम जनता ग्राम अधिना को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदक - लीलावली मिंज आ0 शंकर मिंज जाति उरांव निवासी ग्राम 37 अधिना तहसील भटगांव जिला सूरजपुर द्वारा स्वयं लीलावल मिंज / का जन्म दिनांक 1-1-1985 को जन्म होने पर आवेदक द्वारा स्वयं का जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीयन बावत् शुल्क अदा कर चालान की प्रति, शपथ पत्र, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है।

जिस किसी हितबद्ध पक्षकार को कोई आक्षेप हो तो वह अपना आक्षेप दिनांक 30/04/2026 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं तद्नुसार कार्यवाही कर दी जावेगी । आज दिनांक 16/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
भटगांव
(सील) **जिला-सूरजपुर,छ0ग0**

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगांव,तहसील-भटगांव

रा0प्र0क्र0 /ब-121/2025-26

ईश्तहार

आम जनता ग्राम कपसरा को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रसाद आ0 लक्ष्मण जाति रजवार निवासी ग्राम कपसरा तहसील भगांव जिला सूरजपुर द्वारा अपने माता जिरमेन का मृत्यु दिनांक 17/04/2004 को मृत्यु होने पर आवेदक द्वारा अपने माता का मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीयन बावत शुल्क अदा कर चालान की प्रति, शपथ पत्र, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है।

जिस किसी हितबद्ध पक्षकार को कोई आक्षेप हो तो वह अपना आक्षेप दिनांक 30/04/2026 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं तद्नुसार कार्यवाही कर दी जायेगी।

आज दिनांक 16/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
भटगांव
(सील) **जिला-सूरजपुर,छ0ग0**

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगांव,तहसील-भटगांव

रा0प्र0क्र0 /ब-121 वर्ष
ग्राम-बतरा प0ह0नं0-31

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुशील शर्मा पिता स्व0- अयोध्या प्रसाद शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम. बतरा प.ह.न. 31 रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पिता स्व. अयोध्या प्रसाद शर्मा का मृत्यु दिनांक 13/04/2015 को ग्राम बतरा में हुई है, अज्ञानतावश मृत्यु पंजीयन नहीं करा पाया है। आवेदक अपने पिता स्व. अयोध्या प्रसाद शर्मा का मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत बतरा को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 30/04/26 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा ।

आज दिनांक 16/04/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
भटगांव
(सील) **जिला-सूरजपुर,छ0ग0**

स्पष्टीकरण या सवालों से बचने की कोशिश ? नहर में बहते पानी पर विभाग की सफाई से बढ़ा विवाद

'तकनीकी प्रक्रिया' या पानी की बर्बादी? विभाग की सफाई के बाद भी सवाल बरकरार

- जीर्णोद्धार कार्य के बीच नहर में जल प्रवाह पर विभाग ने दी सफाई...
- एलबीसी नहर में बहते पानी पर विभाग का बयान,कहा...सामान्य डिस्चार्ज
- किसानों की शिकायतों के बाद विभाग का जवाब,पानी बहाव को बताया तकनीकी जरूरत
- भांडी-जनकपुर नहर मामला में खबर के बाद विभाग ने जारी किया विस्तृत स्पष्टीकरण
- 'फ्लशिंग और क्यूरिंग का हिस्सा है पानी' विभाग ने खारिज किए वेस्टेज के आरोप
- नहर में पानी बहने पर मचा था हंगामा,अब विभाग ने दी सफाई

5 करोड़ के जीर्णोद्धार के बीच पानी बहाव पर विभाग का पक्ष सामने आया

आधी-अधूरी जानकारी का आरोप,विभाग ने बताया—नहर का जल प्रवाह तकनीकी प्रक्रिया

नहर में बहते पानी पर विभाग का स्पष्टीकरण, पुराने समाचार के बाद जारी हुआ स्पष्टीकरण

-राजन पाण्डेय-

कोरिया,28 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
भांडी-जनकपुर क्षेत्र की नहर में बहते पानी को लेकर प्रकाशित खबर के बाद जल संसाधन विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण ने विवाद को शांत करने के बजाय और अधिक सवाल खड़े कर दिए हैं,विभाग ने इसे 'तकनीकी प्रक्रिया' और 'सामान्य डिस्चार्ज' बताया है, लेकिन जमीनी हकीकत, स्थानीय किसानों की शिकायतें और दृश्य साक्ष्य इस दावे पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं। भांडी-जनकपुर क्षेत्र की नहर में पानी बहने को लेकर हाल ही में प्रकाशित समाचार के बाद जल संसाधन विभाग, बैकुंठपुर द्वारा विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया गया है,पूर्व में प्रकाशित खबर में नहर में बहते पानी को लेकर स्थानीय स्तर पर असंतोष और सवाल सामने आए थे,किसानों और ग्रामीणों ने इसे पानी की बर्बादी बताते हुए विभागीय कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाए थे,अब विभाग ने पूरे मामले को स्पष्ट करते हुए इसे तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा बताया है और कहा है कि नहर में बहता पानी अनावश्यक वेस्टेज नहीं, बल्कि निर्धारित इंजीनियरिंग व्यवस्था के तहत किया जा रहा सामान्य डिस्चार्ज है, नहर में बहते पानी को लेकर उठे विवाद पर जल संसाधन विभाग ने स्पष्टीकरण देते हुए इसे तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा बताया है, विभाग का दावा है कि यह व्यवस्था अस्थायी है और जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण होने के बाद जल आपूर्ति में सुधार होगा, फिलहाल यह मामला प्रशासनिक पारदर्शिता, तकनीकी प्रक्रियाओं की समझ और जमीनी हकीकत के बीच संतुलन का उदाहरण बनकर सामने आया है, आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि विभाग के दावे कितने प्रभावी साबित होते हैं और क्षेत्र के किसानों को इसका कितना लाभ मिलता है।

क्यों उठा था मामला...

भांडी-जनकपुर क्षेत्र में नहर के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था संचालित होती है,रबी फसल के दौरान कई किसानों ने पानी नहीं मिलने की शिकायत की थी, इसी बीच नहरों में लगातार पानी बहने के दृश्य सामने आए, जिससे यह सवाल उठा कि जब खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा, तो नहरों में पानी क्यों बहाया जा रहा है, पूर्व में प्रकाशित समाचार में इस स्थिति को 'इंजीनियरिंग फेल्योर' बताते हुए विभागीय लापरवाही की ओर संकेत किया गया था, इसके बाद यह मामला चर्चा में आया और विभाग पर स्पष्ट जानकारी देने का दबाव बना।

जमीनी हकीकत ये है की किसान अब भी परेशान

स्थानीय किसानों का कहना है कि रबी फसल के समय पानी नहीं मिला, नहर के पास पानी बहता दिखा,लेकिन खेत सूखे रहे,सूचना पहले दी गई, लेकिन विकल्प नहीं दिए गए,यह स्थिति विभाग के '60% आपूर्ति सामान्य' वाले दावे को कमजोर करती है, बजट और काम की प्रगति पर भी सवाल करीब 5 करोड़ रुपये की परियोजना में अब तक केवल 88 लाख खर्च होना यह संकेत देता है कि कार्य धीमी गति से चल रहा है, प्राथमिकताओं का सही निर्धारण नहीं हुआ, मॉनिटरिंग की गुणवत्ता पर भी प्रश्नचिह्न है?

स्पष्टीकरण से ज्यादा 'बचाव' क्यों लग रहा है बयान?

विभाग का पूरा बयान तकनीकी शब्दों– 'क्यूरिंग ','फ्लशिंग ', 'डिस्चार्ज '–से भरा हुआ है, लेकिन आम जनता के मूल सवालों का सीधा जवाब नहीं देता पानी बह क्यों रहा था? किसानों को क्यों नहीं मिला? खराबी को समय पर ठीक क्यों नहीं किया गया?

जवाब से ज्यादा जवाबदेही की जरूरत

यह मामला केवल एक नहर या पानी के बहाव का नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक जवाबदेही और संसाधनों के प्रबंधन का सवाल है, यदि पानी वास्तव में 'तकनीकी प्रक्रिया' का हिस्सा था, तो इसकी स्पष्ट जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई? और यदि यह लापरवाही थी, तो जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जा रही? फिलहाल, विभाग का स्पष्टीकरण विवाद को शांत करने के बजाय यह संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं 'इंजीनियरिंग फेल्योर' को शब्दों की आड़ में छिपाने की कोशिश हो रही है, अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में पारदर्शिता लाता है या यह भी एक फाइल में दबकर रह जाता है।

विभाग का पक्ष तकनीकी कारणों से हो रहा जल प्रवाह

जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता ने स्पष्ट किया है कि एलबीसी (लेफ्ट बैंक कैनाल) मुख्य नहर का मेन गेट खराब हो गया है, जिसके कारण पानी को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है, इस तकनीकी समस्या के चलते पानी का एक निश्चित बहाव बनाए रखना आवश्यक हो गया है, इसके अलावा नहर के आरडी 6,945 मीटर से 14,700 मीटर तक जीर्णोद्धार कार्य जनवरी 2026 से जारी है, इस कार्य के अंतर्गत नहर की संरचना को मजबूत करने, रिसाव रोकने और जल वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, विभाग ने बताया कि मरम्मत कार्य के दौरान पानी के प्रवाह को संतुलित रखने के लिए अस्थायी एस्केप (निकासी मार्ग) का निर्माण किया गया है,यह व्यवस्था पूरी तरह अस्थायी है और कार्य पूर्ण होने के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा,अधिकारी के अनुसार यदि नहर में पानी का बहाव पूरी तरह रोक दिया जाए,तो इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और नहर की संरचना को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है,विभाग ने आगे कहा कि नहर में बहता पानी कई तकनीकी प्रक्रियाओं का हिस्सा है, जिनमें प्रमुख रूप से फ्लशिंग (नहर की सफाई),सिल्ट नियंत्रण (गाद को हटाना),क्यूरिंग (निर्माण कार्य को मजबूत बनाना) शामिल हैं,इन प्रक्रियाओं के दौरान पानी का बहाव आवश्यक होता है,ताकि नहर की संरचना टिकाऊ बन सके और भविष्य में जल आपूर्ति बेहतर तरीके से की जा सके।

टेल-एंड क्षेत्रों को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना

विभाग के अनुसार यह पूरी व्यवस्था केवल वर्तमान स्थिति के लिए नहीं,बल्कि भविष्य की जल आपूर्ति को ध्यान में रखकर बनाई गई है, नहर के टेल-एंड (अंतिम छोर) क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने के लिए फ्लो मैनेजमेंट जरूरी है,यदि इस दौरान पानी का प्रवाह पूरी तरह रोक दिया जाता,तो आगे चलकर जल वितरण असंतुलित हो सकता था,इसलिए तकनीकी मानकों के अनुसार पानी का डिस्चार्ज बनाए रखा गया है।

जल आपूर्ति की वर्तमान स्थिति

विभाग ने दावा किया है कि वर्तमान में कमांड एरिया के लगभग 60 प्रतिशत हिस्से में जल आपूर्ति सामान्य रूप से हो रही है,हालांकि शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में जीर्णोद्धार कार्य के कारण पानी की आपूर्ति प्रभावित है,विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में कार्य पूर्ण होने के बाद जल आपूर्ति नियमित कर दी जाएगी,साथ ही संबंधित पंचायतों को पहले ही रबी सीजन के दौरान पानी उपलब्ध नहीं होने की सूचना दी जा चुकी थी।

किसानों की स्थिति और विभाग का रुख

किसानों की शिकायतों को लेकर विभाग ने कहा है कि जल वितरण की योजना पहले से तय होती है और कार्य के दौरान कुछ असुविधाएं स्वाभाविक हैं,विभाग का कहना है कि जिन क्षेत्रों में पानी नहीं दिया जा सका,वहां पूर्व सूचना दी गई थी, ताकि किसान वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें,हालांकि स्थानीय स्तर पर कई किसान इस दावे से सहमत नहीं हैं और उनका कहना है कि उन्हें समय पर पर्याप्त जानकारी नहीं मिली।

परियोजना की लागत और व्यय

नहर के जीर्णोद्धार कार्य के लिए कुल 496.99 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है,विभाग के अनुसार अब तक इस परियोजना में लगभग 88 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं,शेष कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है और इसके लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है,विभाग ने कहा है कि कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

मॉनिटरिंग और प्रशासनिक समन्वय

विभाग ने बताया कि इस परियोजना की निगरानी जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर की जा रही है,नियमित रूप से टैंक गेज रिपोर्ट और लॉगबुक के आधार पर नहर के जल स्तर और प्रवाह की समीक्षा की जा रही है,इसके अलावा उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण भी किया जा रहा है,ताकि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा हो सके।

अस्थायी व्यवस्थाएं होंगी समाप्त

विभाग ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही जीर्णोद्धार कार्य पूरा होगा,सभी अस्थायी एस्केप और कटाव को बंद कर दिया जाएगा, इसके बाद नहर का संचालन पूरी तरह नियंत्रित तरीके से किया जाएगा और पानी की अनावश्यक निकासी नहीं होगी,विभाग का कहना है कि वर्तमान में जो व्यवस्था दिखाई दे रही है,वह केवल निर्माण कार्य के दौरान की अस्थायी स्थिति है।

पूर्व प्रकाशित समाचार पर प्रतिक्रिया

विभाग ने यह भी कहा है कि कुछ समाचारों में अधूरी जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकाले गए थे,जिससे भ्रम की स्थिति बनी, विभाग के अनुसार वास्तविक स्थिति को समझे बिना पानी के बहाव को बर्बादी के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है,विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह जल प्रवाह पूरी तरह तकनीकी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है और इसका उद्देश्य भविष्य में बेहतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

जमीनी स्तर पर स्थिति पर नजर

हालांकि विभाग ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति पर नजर बनाए रखने की जरूरत बनी हुई है,किसानों और स्थानीय लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कार्य समय पर पूरा होता है या नहीं और जल आपूर्ति में वास्तविक सुधार आता है या नहीं।

लेकिन सवाल यहीं से शुरू होते हैं...

विभाग के इस स्पष्टीकरण को लेकर कई बुनियादी प्रश्न उठ रहे हैं...

'मेन गेट खराब' तो जिम्मेदारी किसकी?

यदि मुख्य गेट पहले से खराब था, तो उसकी मरम्मत प्राथमिकता क्यों नहीं बनी? क्या इतनी बड़ी परियोजना में यह लापरवाही नहीं मानी जाएगी?

तकनीकी प्रक्रिया या पानी की बर्बादी?

जिसे विभाग 'फ्लशिंग' और 'डिस्चार्ज' बता रहा है, वही पानी खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा, किसानों का कहना है कि उन्हें सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला, जबकि नहरों में पानी बहता दिख रहा है।

अस्थायी एस्केप या स्थायी लापरवाही?

एस्केप निर्माण को अस्थायी बताया गया है, लेकिन सवाल है की क्या इस व्यवस्था की पहले से कोई योजना थी या यह खराब प्रबंधन का तात्कालिक समाधान है?

आधी-अधूरी जानकारी किसकी?

विभाग ने मीडिया रिपोर्ट्स को 'तथ्य से परे' बताया,लेकिन क्या विभाग ने पहले कभी पारदर्शी तरीके से यह जानकारी सार्वजनिक की थी?

दिवंगत प्रधान आरक्षक की पत्नी को अनुकम्पा नियुक्ति,महिला आरक्षक के पद पर मिली नौकरी

-संवाददाता-

सूरजपुर,28 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
सूरजपुर जिले में दिवंगत प्रधान आरक्षक जवाहर लाल सिंह की पत्नी दुर्गावती सिंह को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है,डीआईजी एवं एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने सोमवार को उन्हें महिला आरक्षक के पद पर नियुक्त किया, सेवा के दौरान प्रधान आरक्षक जवाहर लाल सिंह की आकस्मिक मृत्यु के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा ने अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए थे,इसी के तहत आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर दुर्गावती सिंह को नियुक्ति प्रदान की गई,नियुक्ति के दौरान डीआईजी व एसएसपी ने दुर्गावती सिंह से चर्चा की और उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली,इस दौरान उन्होंने आवास की जरूरत बताई, जिस पर उन्हें जल्द ही आवास उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया, इस अनुकम्पा नियुक्ति से दिवंगत कर्मचारी के परिवार को सहारा मिला है, पुलिस विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई कर नियुक्ति देने को संवेदनशील पहल माना जा रहा है।

कोरिया जिला औषधि विक्रेता संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

जांच में पुलिस का दखल सिर्फ विशेष परिस्थितियों में हो

-संवाददाता-

बैकुंठपुर,28 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
कोरिया जिला औषधि विक्रेता संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार,27 अप्रैल को जिला अध्यक्ष शैलेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में कलेक्टर कोरिया से मुलाकात की इस दौरान मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य सचिव के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया,जिसमें प्रदेश शासन द्वारा गठित 'संयुक्त जांच दल' की कार्यप्रणाली को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं।

प्रमुख मांग : भयमुक्त व्यापारिक वातावरण- ज्ञापन के माध्यम से संघ ने निवेदन किया है कि प्रदेश शासन द्वारा गठित जांच दलों में पुलिस बल को केवल शिकायत या अत्यंत संदेह की विशेष परिस्थितियों में ही शामिल किया जाए,संघ का मानना है कि नियमित जांच के दौरान पुलिस की उपस्थिति से व्यापारियों में अनावश्यक भय का माहौल बनता है,जिससे सामान्य व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं।

कलेक्टर महोदया का आश्वासन- प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई चर्चा अत्यंत सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण रही। माननीय कलेक्टर महोदया ने औषधि विक्रेताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि आम केमिस्टों को भयभीत होने की कतई आवश्यकता नहीं है, प्रशासन का उद्देश्य नियमों का पालन सुनिश्चित करना है, किसी को परेशान करना नहीं।

संघ का पक्ष : अवैध व्यापार पर 'जीरो टॉलरेंस'- चर्चा के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि समय-समय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा होने वाली नियमित जांच में संघ हमेशा पूर्ण सहयोग करता है,औषधि विक्रेता संघ किसी भी प्रकार के अवैध व्यापार को संरक्षण प्रदान नहीं करता है,संघ प्रशासन के साथ मिलकर रचनात्मक कार्यों में सहयोग के लिए हमेशा कृतसंकल्पित है।

प्रतिनिधिमंडल में ये रहे मौजूद- इस अवसर पर सचिव नंदकिशोर रजवाड़े, शशांक जिज्ञासी,ज्ञान प्रकाश गुप्ता, रणविजय गुप्ता,धीरज मिश्रा,दिनेश सिंह,जितेंद्र सिंह, राकेश गुप्ता,शैलेन्द्र गुप्ता,चिराग,अनुपम गुप्ता, राकेश तिवारी,सौरभ गुप्ता और अशोक बंजारे सहित संघ के अन्य सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

'सरकारी पैसा है...' जिसे महंगे उपकरणों की खरीदी पर उठे सवाल, विभागीय खर्च पर फिर घिरा तंत्र?

कोरिया शिक्षा विभाग का 1.80 करोड़ प्रोजेक्ट सवालों में,भ्रष्टाचार के आरोप पर जांच की मांग

बाहरी कंपनी को करोड़ों का ठेका,स्थानीय विक्रेताओं की अनदेखी—कलेक्टर से शिकायत

स्कूल 'रूम मेकओवर' प्रोजेक्ट में अनियमितता का आरोप,भुगतान रोकने की मांग

टेंडर प्रक्रिया पर उठे सवाल,महंगे सौदों से सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप

-राजन पाण्डेय-

कोरिया,28 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। सरकारी खर्चों को लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर अक्सर बहस होती रही है, लेकिन हालिया खरीदी ने इस मुद्दे को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है, विभाग द्वारा कार्यालय उपयोग के नाम पर ऐसे उपकरण खरीदे गए हैं, जिनकी कीमत बाजार दर से काफी अधिक बताई जा रही है, आमतौर पर जिन वाई-फाई राउटर और प्रोजेक्टर को लोग अपने घरों या निजी संस्थानों के लिए कम कीमत में खरीद रहे हैं, वही उपकरण सरकारी दफ्तरों में कई गुना महंगे दाम पर खरीदे जाने की जानकारी सामने आई है,इस पूरे मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकारी धन के उपयोग में वास्तव में सावधानी बरती जा रही है या 'सरकारी पैसा है' की सोच के कारण अनावश्यक खर्च को नजरअंदाज किया जा रहा है। बता दे की जिला कोरिया के स्कूल शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपये के एक प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, कलेक्टर को सौंपे गए एक विस्तृत शिकायत पत्र में न केवल प्रक्रियागत अनियमितताओं,बल्कि संभावित भ्रष्टाचार और मिलीभगत तक के आरोप लगाए गए हैं, शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, भुगतान पर तत्काल रोक और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा हाल ही में कुछ तकनीकी उपकरणों की खरीदी की गई है, जिसमें वाई-फाई राउटर और प्रोजेक्टर प्रमुख हैं, इन उपकरणों की खरीदी को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, वे सामान्य बाजार दरों से मेल नहीं खाते, बताया जा रहा है कि एक वाई-फाई राउटर की कीमत लगभग 18,500 रुपये दिखाई गई है, जबकि बाजार में इसी श्रेणी के राउटर आमतौर पर 4,000 से 5,000 रुपये के बीच आसानी से उपलब्ध हैं, इसी तरह एक प्रोजेक्टर की खरीदी करीब 90,000 रुपये में की गई है, जबकि वर्तमान समय में अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोजेक्टर 40,000 से 45,000 रुपये के बीच उपलब्ध हो जाते हैं।

1.80 करोड़ का प्रोजेक्ट बना विवाद की जड़

शिकायत के अनुसार जिला शिक्षा कार्यालय कोरिया द्वारा 'शिल्पमिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड' सूरत (गुजरात) को लगभग 1,80,84,535 का प्रोजेक्ट सौंपा गया है, यह प्रोजेक्ट स्कूलों में 'Room Makeover ',डिजिटल उपकरणों की आपूर्ति और अन्य तकनीकी कार्यों से जुड़ा बताया गया है, शिकायतकर्ता का आरोप है कि इतनी बड़ी राशि का काम देने में पारदर्शिता नहीं बरती गई और नियमों को दरकिनार किया गया।

बाहरी कंपनी को लाभ,स्थानीय व्यापारियों की अनदेखी

शिकायत पत्र में सबसे बड़ा मुद्दा यह उठाया गया है कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय अनुभवी विक्रेताओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर एक बाहरी कंपनी को काम दे दिया गया, आरोप है कि स्थानीय व्यापारियों को मौका नहीं दिया गया, बाहरी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, इससे स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक असर पड़ेगा, साथ ही यह भी कहा गया है कि भविष्य में सर्विस और मेंटेनेंस के लिए बाहरी कंपनी पर निर्भरता बढ़ेगी, जिससे अतिरिक्त खर्च और परेशानी हो सकती है।

बिना स्पष्ट सूची के स्वीकृत हुआ काम

शिकायत में यह भी उल्लेख है कि जिन स्कूलों में 'रूम मेकओवर' किया जाना है, उनकी स्पष्ट सूची तक उपलब्ध नहीं है,इसके बावजूद लगभग 23 लाख के कार्य का प्रावधान कर दिया गया, जिसे नियमों के विपरीत और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बताया गया है।

बाजार दर से कई गुना अधिक कीमतें

प्रोजेक्ट में शामिल सामग्रियों की कीमतों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं,शिकायत के अनुसार WiFi Router की कीमत लगभग 18,500 दिखाई गई, Projector की कीमत लगभग 90,000 बताई गई, जो कि सामान्य बाजार दर से 200 से 300 प्रतिशत अधिक बताई जा रही है। इसे सीधे तौर पर सरकारी धन के दुरुपयोग से जोड़ा जा रहा है।

'हैदराबाद मीटअप' खर्च पर भी विवाद

शिकायत में 'हैदराबाद मीटअप' के नाम पर किए गए खर्च को भी संदिग्ध बताया गया है, बताया गया है कि 10 शिक्षकों के लिए 1.01 लाख प्रति व्यक्ति का प्रावधान किया गया,जिसे अत्यधिक और अनावश्यक खर्च करार दिया गया है,शिकायतकर्ता का कहना है कि इस तरह के खर्च सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ हैं।

मिलीभगत के संकेत,जांच की मांग तेज

शिकायत में विभाग और संबंधित कंपनी के बीच संभावित मिलीभगत की भी आशंका जताई गई है, इसी आधार पर कलेक्टर से मांग की गई है कि पूरे प्रोजेक्ट का भौतिक सत्यापन कराया जाए,कंपनी को किए जा रहे सभी भुगतानों पर तत्काल रोक लगाई जाए,टेंडर प्रक्रिया और दर निर्धारण की निष्पक्ष जांच हो,दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

उच्च स्तर पर भेजी गई शिकायत

मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन,शिक्षा मंत्री,एंटी करप्शन ब्यूरो, स्थानीय विधायक,प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को भी भेजी गई है,ताकि उच्च स्तर पर निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती

इस पूरे मामले ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं,यदि आरोप सही पाए जाते हैं,तो यह न केवल आर्थिक अनियमितता का मामला होगा,बल्कि सरकारी व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी गंभीर असर डालेगा।

बाजार दर और विभागीय खरीदी में बड़ा अंतर

स्थानीय बाजार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कीमतों की तुलना करने पर यह अंतर और स्पष्ट हो जाता है,तकनीकी जानकारों का कहना है कि सामान्य कार्यालय उपयोग के लिए जिस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है,वे मध्यम श्रेणी में ही आसानी से उपलब्ध होते हैं,ऐसे में दोगुनी या उससे अधिक कीमत पर खरीदी को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है,विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यदि कोई विशेष उच्च गुणवत्ता या विशेष फीचर्स वाला उपकरण खरीदा गया हो,तो उसकी तकनीकी जानकारी और औचित्य सार्वजनिक किया जाना चाहिए,ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

शिक्षा विभाग में 'मिलीभगत' के संकेत,करोड़ों के प्रोजेक्ट की जांच की मांग तेज

बाजार से 200-300% ज्यादा दरों पर खरीदी का आरोप

1.80 करोड़ के प्रोजेक्ट में पारदर्शिता पर उठे सवाल

'अपने घर के लिए खरीदते तो '—उठ रहा बड़ा सवाल

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि यदि यही उपकरण संबंधित अधिकारी अपने निजी उपयोग के लिए खरीदते, तो क्या वे इतनी अधिक कीमत पर इन्हें खरीदते? सामान्य तौर पर देखा जाता है कि निजी उपयोग के लिए लोग बाजार में उपलब्ध विकल्पों की तुलना करते हैं और कम कीमत में बेहतर गुणवत्ता का सामान खरीदने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब बात सरकारी खरीद की आती है, तो कई बार यही सावधानी नहीं बरती जाती, स्थानीय लोगों का कहना है कि 'यदि यह खरीदी निजी पैसों से होती, तो निश्चित रूप से इतनी महंगी नहीं होती।

नियम और प्रक्रिया क्या कहते हैं...

सरकारी विभागों में किसी भी प्रकार की खरीदी के लिए निर्धारित नियम और प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें निविदा (टेंडर) प्रक्रिया, दरों की तुलना,गुणवत्ता परीक्षण और स्वीकृति जैसे कई चरण शामिल होते हैं,इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकारी धन का उपयोग पारदर्शी और उचित तरीके से किया जाए, हालांकि,जब इस प्रकार की महंगी खरीदी के मामले सामने आते हैं,तो यह सवाल उठता है कि क्या इन सभी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन किया गया था या नहीं,सूत्रों के अनुसार,इस खरीदी में टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर भी चर्चा हो रही है,यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितनी कंपनियों ने इसमें भाग लिया और किन मानकों के आधार पर चयन किया गया, यदि प्रतिस्पर्धी दरों की तुलना की गई होती,तो संभवतः कम कीमत में भी वही उपकरण खरीदे जा सकते थे,विशेषज्ञों का मानना है कि ई-प्रोक्योरमेंट और जेम जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदी करने पर दरों में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बनी रहती है।

गुणवत्ता बनाम कीमत—क्या था आधार

विभागीय स्तर पर अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिक कीमत वाले उपकरण खरीदे जाते हैं, लेकिन इस मामले में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि खरीदे गए उपकरणों में ऐसा कौन-सा विशेष फीचर या तकनीकी क्षमता है, जो उन्हें सामान्य बाजार उत्पादों से अलग बनाती है, यदि कीमत अधिक है, तो उसके पीछे ठोस तकनीकी कारण होना चाहिए, अन्यथा इसे अनावश्यक खर्च माना जा सकता है।

जनता के बीच बढ़ती नाराजगी

इस मामले के सामने आने के बाद आम लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, लोगों का कहना है कि एक तरफ जहां आम नागरिकों को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ती है, वहीं सरकारी स्तर पर इस तरह के खर्च जनता के पैसे का दुरुपयोग प्रतीत होते हैं,कई लोगों ने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए धन की कमी की बात कही जाती है,लेकिन दूसरी ओर इस तरह की महंगी खरीदी समझ से परे है।

पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग...

इस पूरे मामले में अब पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग तेज हो गई है, स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि इस खरीदी की जांच होनी चाहिए और यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि खरीदी किस प्रक्रिया के तहत की गई,दरों का निर्धारण कैसे हुआ, क्या बाजार दरों की तुलना की गई थी और क्या इसमें किसी प्रकार की अनियमितता हुई है?

विभाग की चुप्पी या जवाब का इंतजार

फिलहाल इस मामले में संबंधित विभाग की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है,हालांकि,सूत्रों का कहना है कि विभाग इस मामले की आंतरिक समीक्षा कर सकता है,यदि विभाग की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया जाता है,तो इससे स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

विशेषज्ञों की राय

वित्तीय और प्रशासनिक विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी खरीदी में पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, उनका मानना है कि सभी खरीदी प्रक्रियाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए,ई-टेंडरिंग को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और हर बड़ी खरीदी का ऑडिट होना चाहिए,इससे न केवल अनियमितताओं पर रोक लगेगी,बल्कि जनता का विश्वास भी मजबूत होगा।

क्या हो सकती है आगे की कार्रवाई...

यदि इस मामले में अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, इसमें विभागीय जांच, अनुशासनात्मक कार्रवाई या अन्य कानूनी कदम शामिल हो सकते हैं, इसके अलावा, भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं।

सवाल सिर्फ कीमत का नहीं,व्यवस्था का है...

यह मामला केवल महंगे उपकरणों की खरीदी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही का बड़ा प्रश्न बनकर सामने आया है, जब बाजार में उपलब्ध समान उपकरण कम कीमत में मिल रहे हैं, तो अधिक कीमत पर खरीदी को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है, अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विभाग इस मामले में क्या स्पष्टीकरण देता है और क्या वास्तव में इस पर कोई ठोस कार्रवाई होती है या नहीं, फिलहाल इतना जरूर है कि इस मुद्दे ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि 'सरकारी पैसा' आखिर किस हद तक जिम्मेदारी के साथ खर्च किया जा रहा है।

जांच से ही खुलेगा सच...

- क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी?
- क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी?
- या फिर मामला भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा?

बैकुण्ठपुर में भाजपा महिला मोर्चा का जन आक्रोश महिला सम्मेलन सम्पन्न....

-संवाददाता-

बैकुण्ठपुर,28 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। भारतीय जनता पार्टी (भारतीय जनता पार्टी) महिला मोर्चा द्वारा वार्ड क्रमांक-01 हर्रापारा में 'जन आक्रोश महिला सम्मेलन' का आयोजन उत्साह और व्यापक भागीदारी के साथ सम्पन्न हुआ,कार्यक्रम का आयोजन महिला सशक्तिकरण को समर्पित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में किया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान को मजबूत करना रहा, इस सम्मेलन का आयोजन महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष विभा अवस्थी एवं भाजपा जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष वंदना राजवाड़े मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं, जबकि अध्यक्षता महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रीता यादव ने की।

महिलाओं की भागीदारी और उत्साह-कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं और स्थानीय महिलाओं ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और राजनीतिक सहभागिता को लेकर खास उत्साह देखने को मिला,मंच संचालन जिला महामंत्री पुष्पलता राजवाड़े द्वारा किया गया।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर जोर-मुख्य अतिथि वंदना राजवाड़े ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लागू नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कदम है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, उन्होंने इसे 'नारी शक्ति का महायज्ञ' बताते हुए कहा कि यह देश की राजनीति और भविष्य दोनों को नई दिशा देगा,महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रीता यादव ने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करेगा और छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए गर्व का विषय है।

भाजपा की योजनाओं पर चर्चा-जिला कार्यालय मंत्री मंजू जिवनानी ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी क्षमता सिद्ध कर रही हैं और भाजपा सरकार ने उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं, प्रदेश सोशल मीडिया सह प्रभारी रेणु सिंह ने भी कहा कि महिलाएं आज समाज के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य धर्मवती राजवाड़े ने इस सम्मेलन को महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का सशक्त माध्यम बताया।

जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर पहुंचाने का आह्वान-मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी राजवाड़े ने सभी महिला कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया, कार्यक्रम संयोजक एवं जिला मंत्री आंचल सिंह ने कहा कि यह अधिनियम केवल कानून नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।

बड़ी संख्या में महिलाएं रहीं उपस्थित-इस अवसर पर कई महिला कार्यकर्ता और स्थानीय महिलाएं मौजूद रहीं, जिनमें शीला मिश्रा,अनिता मिश्रा,आशा देवी, किरण शर्मा,रूपा मिश्रा,राजकुमारी मिश्रा, आरती सिंह,तारा साहू,उमा परवार,सरिता कश्यप,भुनेश्वरी राजवाड़े,सोनू सिंह सहित अन्य शामिल थीं।

भाजपा जिला कोरिया में मोर्चा प्रभारियों की नियुक्ति,संगठन को मिलेगी नई धार

-संवाददाता-

बैकुण्ठपुर,28 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। भारतीय जनता पार्टी जिला कोरिया में संगठनात्मक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए विभिन्न मोर्चों के जिला प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, यह निर्णय भाजपा जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी द्वारा प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार लिया गया, जिसका उद्देश्य संगठन के विभिन्न मोर्चों के कार्यों को अधिक प्रभावी, सक्रिय और समन्वित बनाना है।

विभिन्न मोर्चों के लिए नियुक्त प्रभारी

नवीन नियुक्तियों के तहत अलग-अलग मोर्चों की जिम्मेदारी अनुभवी एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है–

- युवा मोर्चा - अनीता तिवारी
- किसान मोर्चा - विनोद साहू, नवरत्न पाण्डेय
- महिला मोर्चा - तीरथ राजवाड़े
- ओबीसी मोर्चा - रविशंकर राजवाड़े, कृष्णावती यादव
- अजजा (जनजाति) मोर्चा - अनिल साहू, गायत्री सिंह
- अजा (अनुसूचित जाति) मोर्चा - शारदा गुप्ता, मनोज सोनवानी
- अल्पसंख्यक मोर्चा - परमजीत कौर

संगठन को मिलेगी नई ऊर्जा-इन नियुक्तियों के साथ भाजपा जिला कोरिया में संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है,पार्टी नेतृत्व का मानना है कि जमीनी स्तर पर कार्यों के बेहतर संचालन और समन्वय से संगठन और अधिक मजबूत होगा,जिला संगठन ने सभी नवनियुक्त प्रभारियों को शुभकामनाएं देते हुए अपेक्षा व्यक्त की है कि वे पार्टी की रीति-नीति और विचारधारा के अनुरूप समर्पण भाव से कार्य करेंगे तथा संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

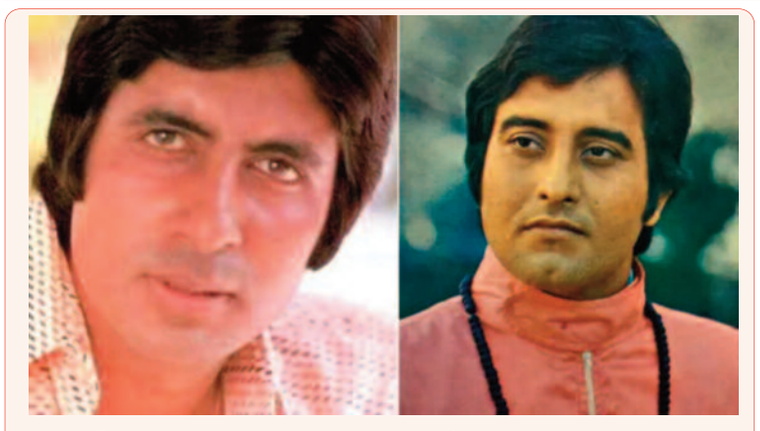

अमिताभ बच्चन से क्यों जल-भुन गए थे विनोद खन्ना?

ओशो ने पढ़ ली थी दयावान एक्टर के मन की बात

विनोद खन्ना ने करियर के पीक पर बॉलीवुड छो कर सादा जीवन जीने का निर्णय लिया था और वह ओशो के आश्रम में चले गए थे। इसके बावजूद बिग बी के प्रति उनके अंदर इर्ष्या पैदा हो गई थी। विनोद खन्ना ने अपने स्टारडम के चरम पर कई ऐसे फैसले लिए, जिन्होंने उन्हें अपने दौर के एक्टर्स से लोकप्रियता में पीछे कर दिया। साल 1975 में आध्यात्मिक गुरु ओशो (श्री रजनीश) से दीक्षा लेने के बाद विनोद खन्ना ने करियर के पीक पर 1982 में पूरी तरह से बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। जहां वह एक आश्रम में रहने लगे और खुद को स्वामी विनोद भारती का नाम दिया।सबकुछ छोड़कर एक सादगी भरी जिंदगी जीने पहुंचे विनोद खन्ना आखिर आश्रम में रहकर भी क्यों गुमसुम और दुखी रहते थे और साथ ही उन्हें अमिताभ बच्चन से जलन क्यों होने लगी थी? अभिनेता से जुड़ा यह किस्सा ओशो के भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती ने शेयर किया था।

अमिताभ बच्चन के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की मिली सलाह

ओशो के भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती ने पिंकविला की हिंदी वेबसाइट को दिए एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, ÷उन्होंने देखा कि विनोद दुखी हैं और अपने आसपास के लोगों से पूछा कि उन्हें क्या चीज परेशान कर रही है? कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें अपने परिवार की याद आ रही है, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, उन्हें परिवार की याद नहीं आ रही है। उनसे कहो कि वह भारत वापस जाएं और अमिताभ बच्चन के खिलाफ इलेक्शन लड़ें। मैं यह कभी सोच भी नहीं सकता था कि उनकी राजनीति में जाने की चाहत है, लेकिन ओशो के पास वह अंतर्दृष्टि थी।

अमिताभ बच्चन से मन ही मन जलने लगे थे विनोद खन्ना

स्वामी शैलेंद्र सरस्वती ने यह भी बताया था कि विनोद खन्ना से जुड़ी जो चीज वह नहीं देख पा रहे थे, उसे ओशो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ चुके थे। उन्हें यह बहुत ही अच्छे से समझ आ गया था कि विनोद खन्ना को परिवार से दूर होने का दर्द नहीं है, बल्कि उन्हें अपना स्टेटस खोने की पीड़ा है। उन्होंने बॉलीवुड तब छोड़ा था जब वह अपने करियर के पीक पर थे और उनकी अनुपस्थिति में अमिताभ बच्चन नंबर 1 स्टार बन चुके थे। विनोद खन्ना ने खुद को यह समझाने की काफी कोशिश की थी कि वह एक नेक इंसान हैं, लेकिन ओशो को यह आभास हो गया था कि उन्हें बॉलीवुड में अपनी टॉप पोजीशन खोने का दर्द है और वह मन ही मन अमिताभ बच्चन से जलने लगे थे, जो कई रूपों में सामने आ रही थी। कुछ सालों तक आश्रम में रहने के बाद साल 1987 में विनोद खन्ना ने फिल्म इंसाफ से बॉलीवुड में शानदार वापसी की। उनकी सत्यमेव जयते और इंसाफ जैसी फिल्में सुपरहिट तो रहीं, लेकिन 5 साल बाद लौटने के बावजूद वह अमिताभ बच्चन से नंबर 1 की पोजीशन नहीं छीन पाए।

24 साल पहले महाफ्लॉप हुई एसआरके-सलमान की फिल्म

दरियादिली दिखाकर नहीं लिए 95 लाख

निर्माता केसी बोकाडिया ने हाल ही में शाहरुख खान के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बात की।
जब 2002 में हम तुम्हारे हैं सनम रिलीज हुई, तो इसने हिंदी सिनेमा के तीन सबसे बड़े सितारों - शाहरुख खान, सलमान खान और माधुरी दीक्षित को एक साथ ला दिया। इतनी चर्चा होने के बावजूद, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बस औसत ही प्रदर्शन कर पाई। दो दशक से भी ज्यादा समय बाद, पर्दे के पीछे की एक दिलचस्प कहानी फिर से सामने आई है - एक ऐसी कहानी जो शाहरुख खान के पर्दे पर निभाए किरदार के बजाय, पर्दे के पीछे किए गए उनके एक नेक काम को उजागर करती है।

पहली ही मुलाकात से इंप्रेस थे प्रोड्यूसर

शाहरुख खान के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए, प्रोड्यूसर के.सी. बोकाडिया ने बताया कि उन्होंने एक्टर से एक साफ और सीधा प्रस्ताव लेकर संपर्क किया था। उन्होंने समझाया कि वह एक तमिल फिल्म का रीमेक बनाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें एक्टर की लगभग 20 दिनों की डेट्स की जरूरत होगी। बोकाडिया ने एक पॉडकास्ट को बताया, मैंने उनसे कहा, मुझे नहीं पता कि आप कितनी फीस लेते हैं, लेकिन मैं इसके लिए आपको 2 करोड़ रुपये देने को तैयार हूं। उन्होंने यह भी बताया कि उस समय शाहरुख खान की आम फीस 1 से 1.5 करोड़ रुपये के बीच हुआ करती थी।

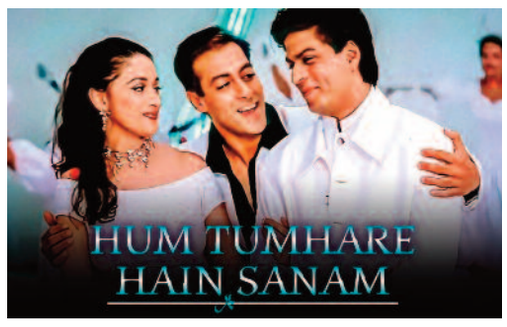

एसआरके ने तुरंत कर दी थी हां

बोकाडिया को जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई, वह थी एक्टर का तुरंत जवाब देना। शाहरुख खान ने इस प्रोजेक्ट पर विचार करने की हामी भरी और अगले ही दिन फिल्म का ओरिजिनल वर्जन देखने के लिए पहुंच गए। उस दिन का एक मजेदार किस्सा सुनाते हुए बोकाडिया ने मजाक में कहा, डायरेक्टर की पर्सनैलिटी थोड़ी अजीब थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि वह स्क्रीनिंग के दौरान अंदर न जाएं, क्योंकि कहीं स्क्रीन उन्हें देखकर ही भाग न जाएं।

बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी फिल्म

सलमान खान और माधुरी दीक्षित जैसे सितारों के होने के बावजूद, फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इस दौरान, बोकाडिया पर शाह रुख खान के 95 लाख रुपये अभी भी बकाया थे। जब प्रोड्यूसर ने बकाया रकम की बात छेड़ी, तो एक्टर ने एक बार फिर अपने जवाब से उन्हें हैरान कर दिया। बोकाडिया ने बताया, मैंने शाहरूख खान से कहा, सर, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा, हमने आपसे पैसों का वादा किया है। यह अच्छा नहीं लगेगा। शाहरूख खान ने कहा, इसकी चिंता मत करो। मैं किसी शादी में सिर्फ 5 मिनट के लिए जाकर ही 95 लाख रुपये कमा सकता हूं। तुम्हें तो मुझे पैसे देने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। भला ऐसा कौन कहता है? यही तो उनका अच्छा स्वभाव है।

फिल्म के बारे में...

खबरों के मुताबिक, हम तुम्हारे हैं सनम को सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले बनने में लगभग छह साल लगे थे। दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म खुद 1995 की तमिल फिल्म थोटा चिनुंनची का रीमेक थी, जिसे के.एस.अधिवमान ने डायरेक्ट किया था। हालांकि हिंदी वर्जन उम्मीदों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरा, फिर भी यह शाहरुख खान और सलमान खान को एक साथ लाने के लिए याद किया जाता है। इन सालों में, दोनों एक्टर्स ने बहुत कम मौकों पर ही एक साथ स्क्रीन शेयर की है, और अक्सर कैमियो रोल में ही नजर आए हैं।

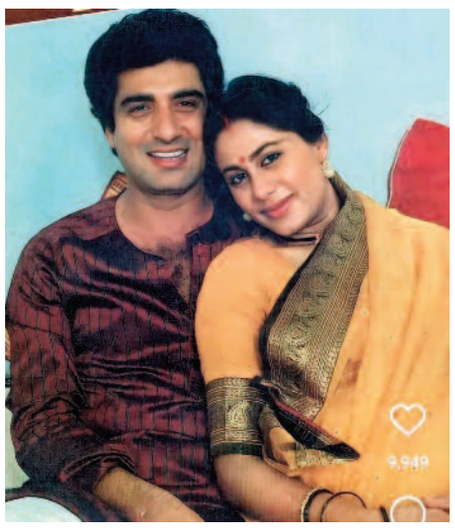

राज बब्बर के प्यार में पूरी तरह पागल थीं स्मिता पाटिल

एकतरफा प्यार भले ही सुनने में अजीब लगता हो लेकिन असल जिंदगी में भी यह होता है भले ही सामने वाला इंसान शादीशुदा ही क्यों ना हो। कुछ ऐसी ही कहानी है स्मिता पाटिल और राज बब्बर की। स्मिता को शादीशुदा राज बब्बर से बेइंतहा प्यार हो गया था और इस वजह सब एक्ट्रेस के खिलाफ हो गए थे,यहां तक कि परिवार वाले भी।

बेटे के जन्म के बाद हुआ निधन

स्मिता पाटिल का निधन बच्चे के जन्म के कुछ ही हफ्तों बाद, 31 साल की उम्र में हो गया था। अरुणा राजे उनकी आखिरी रात को याद करती हैं,जबकि उनके लिखे खत राज बब्बर के लिए उनके गहरे प्यार और उस अकेलेपन को बयां करते हैं, जिसे उन्होंने चुपचाप सहा। स्मिता पाटिल का निधन सिर्फ 31 साल की उम्र में बच्चे के जन्म के बाद हुई कुछ जटिलताओं के कारण हो गया था। उन्होंने 28 नवंबर को राज बब्बर के साथ अपने बेटे प्रतीक का स्वागत किया था। इसके कुछ ही हफ्तों बाद, 13 दिसंबर 1986 को, वह इस दुनिया से चली गईं; अपने पीछे वह एक विरासत और एक नवजात शिशु छोड़ गईं।

शादीशुदा थे राज बब्बर

उनकी करीबी दोस्त और फिल्ममेकर अरुणा राजे ने उन आखिरी पलों को फिर से याद किया है, साथ ही स्मिता की जिंदगी से जुड़ी कुछ बेहद निजी बातें भी बताई हैं। स्मिता के आखिरी दिन बहुत अकेलेपन में गुजरे थे। उनके दोस्त और परिवार वाले उनसे दूर हो गए थे, क्योंकि वह राज के साथ रिश्ते में थीं, जो पहले से ही नादिरा बब्बर से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। फिल्ममेकर ने न सिर्फ स्मिता के प्रोफेशनल सफर से जुड़े किस्से शेयर किए, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी बात की। अरुणा ने बताया कि स्मिता एक ऐसी इंसान जो मजेदार होने के साथ-साथ पूरी तरह से सीधी-सादी भी थीं। अरुणा राजे ने उस दिल तोड़ने वाली रात को भी याद किया, जब स्मिता ने अपनी आखिरी सांस ली थी, और बताया कि कैसे उन्होंने उन्हें अस्पताल में लेटे हुए देखा था, यह जानते हुए कि अब वह कभी दोबारा नहीं उठेंगी।

मेगास्टार चिरंजीवी का मास अवतार बॉबी के डायरेक्शन के लिए लॉक हो गया

मेगास्टार चिरंजीवी और मास डायरेक्टर बॉबी कोली के कॉम्बिनेशन में आने वाले क्रेज़ी प्रोजेक्ट मेगा 158 से एक एक्साइटिंग अपडेट आया है। ब्लॉकबस्टर हिट वाल्थेरू वीरैया के बाद, फैंस के बीच उम्मीदें आसमान छू रही हैं क्योंकि यह जोड़ी एक फिल्म के लिए साथ आ रही है। इस फिल्म के लिए मेगास्टार पर किया गया लुक टेस्ट सक्सेसफुली पूरा हो गया है। इस मौके पर डायरेक्टर बॉबी ने साफ किया कि वह मेगास्टार को और भी पावरफुल मास अवतार में दिखाने वाले हैं और अनाउंस किया कि चिरंजीवी का फाइनल लुक लॉक हो गया है। उन्होंने इस बारे में एक इंटरेस्टिंग फोटो भी शेयर की। दूसरी ओर,पिछले कुछ दिनों में केव्हीएन प्रोडक्शंस के इस प्रोजेक्ट से हाथ खींचने की खबरों पर विराम लगाते हुए, यूनिट ने कन्फर्म किया है कि लोहित एन.के. के.व्ही.एन प्रोडक्शंस के बैनर तले बड़े एम्बिशन के साथ फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म का ग्रैंड मुहूर्त मई में होगा और उसी महीने से रेगुलर शूटिंग शुरू हो जाएगी। एस.एस. थमन फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, जबकि निमिश रवि कैमरा हैंडल कर रहे हैं। कास्ट की बात करें तो, डिंपल हयाती एक ज़रूरी नेगेटिव रोल में दिखेंगी और प्रियामणि से एक खास रोल के लिए बात चल रही है। ऐसा लगता है कि फिल्म के दूसरे हाफ में फ्लैशबैक एपिसोड फिल्म का मेन अट्रैक्शन होंगे। अभी, ऐसी खबरें हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए काकाजी टाइटल पर विचार किया जा रहा है, और जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी।

डार्लिंग 4 के री-रिलीज़ ओपनिंग वीकेंड इंडिया बॉक्स ऑफिस

डार्लिंग 4के अपनी री-रिलीज़ में अच्छा परफॉर्म कर रही है। प्रभास और काजल अग्रवाल स्टारर इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रू.. 7.25 करोड़ की अच्छी ओपनिंग वीकेंड में कमाई की। मूवी ने लगभग रू. 4.70 करोड़ की अच्छी ओपनिंग की थी। इसके अलावा, इसमें कुछ गिरावट भी आई, लेकिन मूवी ने वीकेंड में शानदार कमाई की। ए. करुणाकरण के डायरेक्शन में बनी, डार्लिंग 4के ने निज़ाम से लगभग रू. 3.75 करोड़, आंध्र में रू. 2.20 करोड़ और सीडेड में रू. 45 लाख कमाए, जिससे अकेले अपने होम मार्केट में इसकी कुल कमाई रू. 6.70 करोड़ हो गई। अपने बॉर्डर के बाहर, मूवी ने कर्नाटक से लगभग रू 70 लाख और कमाए, जबकि बाकी इंडियन मार्केट ने कुल कमाई में लगभग 15 लाख का कंट्रीब्यूशन दिया। ओरिजिनली, यह मूवी 2010 में रिलीज़ हुई थी, और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म का दोबारा सफल री-रन हो रहा है, जो बताता है कि फिल्म अब तक कितनी अच्छी बनी है। बेशक, प्रभास का सुपरस्टारडम एक मुख्य वजह है कि फिल्म 16 साल बाद भी दर्शकों को खींच रही है। उम्मीद है कि यह दर्शकों को आगे भी खींचती रहेगी। मौजूदा ट्रेंड्स के आधार पर, फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने ओपनिंग वीक में लगभग रू. 10 करोड़ के आसपास कमाई करने का लक्ष्य रखना चाहिए।

खेल समाचार

सिक्किम के रंगपो से पीएम मोदी ने नॉर्थ-ईस्ट में बीसीसीआई इंडोर क्रिकेट अकादमी का वर्चुअल उद्घाटन किया

गंगटोक,28 अप्रैल 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के रंगपो में स्थित सिक्किम क्रिकेट ग्राउंड में बनी नई इंडोर क्रिकेट एकेडमी से पूरे नॉर्थ-ईस्ट क्षेत्र में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की इंडोर क्रिकेट अकादमियों का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस मौके पर नॉर्थ-ईस्ट के कई राज्यों में एक साथ खेल सुविधाओं के विस्तार की शुरुआत मानी जा रही है। यह कार्यक्रम ऐसे समय में हुआ है जब बीसीसीआई देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में क्रिकेट के विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना इस पहल का मुख्य उद्देश्य बताया गया है। सिक्किम के रंगपो में बनी यह नई इंडोर क्रिकेट एकेडमी आधुनिक सुविधाओं से लैस है,जहां खिलाड़ी हर मौसम में अभ्यास कर सकेंगे। इस एकेडमी का उद्घाटन नॉर्थ-ईस्ट के खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल माध्यम से कई अन्य राज्यों की इंडोर क्रिकेट सुविधाओं को भी जोड़ा गया, जिससे एक साथ पूरे क्षेत्र में इस योजना की शुरुआत हो सकी। नॉर्थ-ईस्ट में लंबे समय से खेल सुविधाओं की कमी महसूस की जा रही थी, खासकर क्रिकेट जैसे खेल में। नई इंडोर एकेडमी के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को तकनीकी प्रशिक्षण, फिटनेस और प्रोफेशनल कोचिंग की सुविधा मिलेगी। इससे क्षेत्र के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस पहल को बीसीसीआई की उस रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें देश के सभी हिस्सों में समान खेल अवसर उपलब्ध कराना शामिल है। नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों को अब तक क्रिकेट के मुख्यधारा ढांचे से दूर माना जाता था, लेकिन इन नई सुविधाओं से स्थिति बदलने की उम्मीद जताई जा रही है।

इंग्लैंड ने टी 20 विश्व कप के लिए टीम घोषित की

18 साल की अनकैप्ड खिलाड़ी को मिला मौका

नई दिल्ली,28 अप्रैल 2026। महिला टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन जून और जुलाई में होना है। इस टूर्नामेंट के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान हो गया है। टूर्नामेंट की मेजबानी इंग्लैंड के पास ही है। टीम में18 साल की स्पिनर टिली कोर्टीन-कोलमैन भी शामिल हैं। उन्होंने अभी तक इंग्लैंड के लिए कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। उन्होंने अबी तक द हंड्रेड में 17 मैच खेले हैं और उसमें 17 विकेट लिए हैं। बाएं हाथ की स्पिनर की इकोनॉमी सिर्फ 6.86 की है। पिछले साल महिला अंडर-19 विश्व कप में उन्होंने 3.34 की इकोनॉमी से रन देकर

उन्होंने 5 मैचों में 8 विकेट लिए थे। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को नैट सीवर ब्रंट की कप्तानी वाली 15-खिलाड़ियों की टीम की घोषणा की। इस टीम में चार्ली डीन को उफकप्तान की जिम्मेदारी मिली है। टीम में इसी वोंग और लॉरेन फिलर भी शामिल हैं, जो अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगी। ये दोनों तेज गेंदबाजी आक्रमण का हिस्सा होंगी, जिसमें लॉरेन बेल, डैनी गिब्सन, फ्रेया केम्प और साइवर-ब्रंट भी शामिल हैं।
महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की टीमः-नैट सीवर ब्रंट (कप्तान), लॉरेन बेल,एलिस कैप्सी,टिली कोर्टीन-कोलमैन, चार्ली डीन,सोफिया डंकली,सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, डैनी गिब्सन,एमी जोन्स,फ्रेया केम्प,हीथर नाइट,लिन्से स्मिथ,इसी वोंग,डैनी व्याट-हॉज।

महिला टी 20 विश्व कप 2026 में इंग्लैंड का शेड्यूल

मेजबान इंग्लैंड की टीम महिला टी20 विश्व कप 2026 के पहले ही मैच में मैदान पर होगी। उसकी टक्कर श्रीलंका से है। 12 टीमों के इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड को ग्रुप बी में रखा गया है। इसमें इंग्लैंड और श्रीलंका के अलावा वेस्टइंडीज, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड की टीमें हैं। 30 जून और 2 जुलाई को सेमीफाइनल मुकाबले होंगे जबकि 5 जुलाई को फाइनल होगा।

जॉन स्टोन्स मैनचेस्टर सिटी छोड़ेंगे

लंदन,28 अप्रैल 2026। इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब मेनचैस्टर सिटी के डिफेंडर जॉन स्टोन्स इस सीजन के अंत में क्लब छोड़ देंगे। क्लब ने मंगलवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। स्टोन्स ने एतिहाद स्टेडियम में करीब एक दशक तक खेलते हुए टीम के लिए कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं। 31 वर्षीय जॉन स्टोन्स 2016 में ईवरटोन से मैनचेस्टर सिटी में शामिल हुए थे। वे मैनेजर पेप गार्डियोला के शुरुआती साइनिंग्स में से एक थे और इसके बाद टीम की डिफेंस लाइन का अहम हिस्सा बन गए। अपने सिटी करियर में उन्होंने अब तक 293 मैच खेले हैं और 19 गोल भी किए हैं, जो एक डिफेंडर के तौर पर उनकी

आक्रामक क्षमता को दर्शाता है। स्टोन्स ने मैनचेस्टर सिटी के साथ एक बेहद सफल दौर देखा है, जिसमें टीम ने इंग्लिश फुटबॉल में अपना दबदबा कायम किया। इस दौरान क्लब ने छह प्रीमियर लीग खिताब और यूईएफए चैंपियंस लीग सहित कई बड़े ट्रॉफी जीते। कुल मिलाकर उन्होंने क्लब के साथ 10 से अधिक ट्रॉफियां अपने नाम कीं, जिससे उनका समय सिटी के इतिहास में बेहद खास बन गया। मेनचैस्टर सिटी इस सीजन में भी ट्रॉफी जीतने की दौड़ में बना हुआ है। क्लब पहले ही लीग कप जीत चुका है और अब प्रीमियर लीग तथा अन्य घरेलू खिताबों की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जॉन स्टोन्स अपने अंतिम सीजन में भी कुछ और सफलताएं जोड़ सकते हैं।

पीवी सिंधु की हार के बाद भारत बाहर

नई दिल्ली,28 अप्रैल 2026। बड़ी उम्मीदों के साथ डेनमार्क गई भारतीय टीम उबर कप से बाहर हो गई। टीम इंडिया अचानक ओलंपिक चैंपियन पीवी सिंधु की हार के साथ घर लौटी। सिंधु ने ग्रुप मैच में चीनी शटलर वांग झियू के सामने हाथ खड़े कर दिए। डबल्स में प्रिया कोन्जेंगबाम-श्रुति मिश्रा की जोड़ी को ली शेंगशु-तान निंग की चीनी जोड़ी ने हरा दिया। इशारानी बरौह और देविका सिहाग की हार के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। महिला शटलरों के लिए उबर कप नाकाम रहा। पीवी सिंधु ने सिंगल्स में कड़ी टक्कर दी लेकिन चीनी दीवार को पार नहीं कर पाईं। वांग झियू के

दमदार खेल की वजह से मैच की शुरुआत में 4-7 से पीछे चल रही सिंधु ने आक्रामक खेल दिखाया और नेट पर जोरदार शॉट खेलते हुए स्कोर 9-9 से बराबर कर दिया। लगातार पांच पॉइंट जीतकर 11-9 से बढ़त बना ली। सिंधु की हार से पहले से ही जूझ रही भारत को प्रिया कोन्जेंगबाम और श्रुति मिश्रा की डबल्स जोड़ी और इशारानी बरौह की सिंगल्स जोड़ी ने भी बाहर कर दिया। तनिषा क्रैस्टो और कविप्रिया सेल्वम को भी झटका लगा। उन्हें झांग शक्सिन और लुओ जुमिन ने 21-10, 21-19, 19-21 से हराया। उबर कप में भारतीय टीम का मुकाबला देविका सिहाग के जू वेनजिंग से हारने के साथ खत्म हो गया।

रायगढ़ में अनोखी शादी...दूल्हा-दुल्हन ने जलते अंगारों पर चलकर की नई जिंदगी की शुरूआत

रायगढ़,28 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक ऐसी शादी की परंपरा सामने आई है,जो जितनी अनोखी है उतनी ही चौंकाने वाली भी। यहां विवाह सिर्फ सात फेरों तक सीमित नहीं रहता,बल्कि दूल्हा-दुल्हन को जलते अंगारों पर चलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी होती है। यह परंपरा दशकों से निभाई जा रही है और आज भी पूरे विश्वास और आस्था के साथ जारी है। जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित बिलासपुर गांव में राठिया परिवार के गंधेल गोत्र में यह परंपरा खास तौर पर निभाई जाती है। शादी के बाद जब दुल्हन को घर लाया जाता है,तो सबसे पहले देवी-देवताओं की पूजा होती है। इसके बाद मंडप में जलते अंगारों की परत बिछाई जाती है, जिस पर दूल्हा-दुल्हन सहित परिवार के सदस्य नंगे पांव चलते हैं। इस अनोखी रस्म से पहले परिवार के कई सदस्य उपवास रखते हैं यहां तक कि पानी तक ग्रहण नहीं करते। मान्यता है कि ऐसा करने से देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और परिवार पर कोई संकट नहीं आता। इस दौरान एक और खास परंपरा निभाई जाती है बकरे की बलि। घर के मुखिया पर 'देवता सवार' होने की मान्यता के बीच पूजा-पाठ के बाद अंगारों को मंडप में फैलाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि अंगारों पर चलने के बावजूद किसी के पैरों में जलन या चोट के निशान नहीं दिखाई देते। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक,यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और इसे छोड़ना अशुभ माना जाता है। उनका मानना है कि अगर यह रस्म नहीं निभाई गई तो देवी-देवता नाराज हो सकते हैं। इस अनोखी शादी को देखने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। बदलते दौर में जहां कई परंपराएं खत्म हो रही हैं, वहीं रायगढ़ का यह गांव आज भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ संजोए हुए है।

राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के पैतृक गांव घर की दीवार पर आप कार्यकर्ताओं ने लिखा 'गद्दार

मुंगेली,28 अप्रैल 2026। आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को लेकर छत्तीसगढ़ का भी सियासी पारा बढ़ गया है। इस फैसले से नाराज आप कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मुंगेली जिले में उनके पैतृक गांव बटहा में घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए घर की दीवार पर 'गद्दार' लिखकर अपना विरोध जताया. जानकारी के मुताबिक, बड़ी संख्या में जुटे आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संदीप पाठक पर धोखाधड़ी और अवसरवाद का आरोप लगाते हुए उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने यह भी लिखा कि संदीप पाठक थिंक टैंक नहीं, सैप्टिक टैंक निकले । कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस पार्टी ने उन्हें पहचान दी,उसे छोड़कर उन्होंने जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। गौरतलब है कि संदीप पाठक को आम आदमी पार्टी में रणनीतिकार के रूप में जाना जाता था. पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

आज 10वीं-12वीं बोर्ड के रिजल्ट आएंगे

रायपुर,28 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ में 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज जारी होगा। इसकी घोषणा शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने की है। शिक्षा मंत्री यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि इंतजार की घड़ियां अब समाप्ति की ओर है। बुधवार दोपहर 2:30 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल के हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम औपचारिक रूप से घोषित किए जाएंगे। यह केवल अंकों की घोषणा नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, अनुशासन और अभिभावकों व शिक्षकों के सतत मार्गदर्शन का प्रतिफल है। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को धैर्य बनाए रखने, परिणाम को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करने और भविष्य की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की शुभकामनाएं। प्रत्येक परिणाम एक नई शुरुआत का संकेत है और हर विद्यार्थी में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं निहित हैं।

भारतमाला मुआवजा केस में ईडी की रेड...रायपुर-धमतरी में 8 ठिकानों पर कार्रवाई

66.9 लाख कैश और 37 किलो चांदी जब्त

धमतरी,28 अप्रैल 2026। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमों ने मंगलवार सुबह रायपुर, अभनपुर, धमतरी और कुरुद स्थित 8 अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दी। जांच एजेंसी को शिकायत मिली थी कि भारतमाला हाईवे प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान मुआवजा राशि में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह जांच कर रही है कि इस 'काले धन' को कहां-कहां खपाया गया है। दिनभर चली तलाशी के दौरान अधिकारियों ने 66.9 लाख कैश और 37.13 किलोग्राम चांदी जब्त की है, जिसमें चांदी की ईंटें और अन्य कीमती सामान शामिल हैं। इसके अलावा कई लैपटॉप, मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क भी बरामद किए गए हैं। जांच एजेंसी को आशंका है कि इन डिजिटल उपकरणों में मुआवजा लेनदेन से जुड़े अहम दस्तावेज और कच्चा हिसाब-किताब मौजूद हो सकता है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के चचेरे भाई भूपेंद्र चंद्राकर के ठिकानों पर देर रात तक छापेमारी की गई थी। साथ ही कुरूद में ही राइस मिलर रौशन चंद्राकर के यहां भी छापा मारा गया था। इसके अलावा अभनपुर में भी ईडी की टीम ने कारोबारी गोपाल गांधी और उसके भाइयों के घर दबिश दी थी। यहां रेड के दौरान अफसरों से बदसलूकी और धक्का-मुक्की की गई। डिप्टी डायरेक्टर की शिकायत पर अभनपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अभनपुर टीआई सत्येंद्र श्याम ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की है।

पूर्व मंत्री के भाई के घर 15 घंटे जांच

अजय चंद्राकर के भाई के घर कार्रवाई की बात करें तो ईडी की टीम सोमवार सुबह करीब 6 बजे भूपेंद्र चंद्राकर के घर पहुंची थी। करीब 15 घंटे तक टीम जांच करती रही। करीब 1 बजे तक टीम कार्रवाई में जुटी रही, जिसके बाद वापस लौट गई। जांच के दौरान टीम अपने साथ दो थैलों में महत्वपूर्ण दस्तावेज, जमीन से जुड़े कागजात, एक मोबाइल और लगभग 8 से 9 लाख रुपये कैश लेकर गई है।

अभनपुर में अफसरों से बदसलूकी

जानकारी के मुताबिक, अभनपुर में ईडी की टीम जब दस्तावेज और अन्य सबूत जुटाने की कार्रवाई कर रही थी,तभी सत्यनारायण गांधी और जय प्रकाश गांधी ने टीम को रोकने की कोशिश की। आरोप है कि दोनों ने ईडी के डिप्टी डायरेक्टर नीरज कुमार सिंह और टीम के अन्य सदस्यों के साथ धक्का-मुक्की की और कार्रवाई में बाधा डाली।

डिप्टी डायरेक्टर ने की शिकायत

अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार और सरकारी काम में बाधा डालने की शिकायत ईडी की ओर से अभनपुर थाने में दर्ज कराई गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

शिकायतों के आधार पर ईडी की जांच

भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में करीब 500 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कृषि भूमि को बैकडेट में गैर-कृषि घोषित कर उसका मुआवजा कई गुना बढ़ाया गया। साथ ही एक ही खसरे की जमीन को कागजों में अलग-अलग हिस्सों में बांटकर अलग-अलग लोगों के नाम पर भुगतान किया गया। ईडी इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में छापेमारी कर करोड़ों की संपत्ति अटैच कर चुकी है।

विशेष सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज

महिला आरक्षण बिल पर सरकार को घेरने की तैयारी, महंत करेंगे विधायकों के साथ चर्चा

रायपुर,28 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रस्तावित विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुधवार को आयोजित होगी। यह बैठक शाम को राजीव भवन में होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत विधायकों के साथ रणनीति तय करेंगे। बैठक में विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण और महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की योजना बनाई जाएगी। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज भी मौजूद रहेंगे।

सरकार लाएगी विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव : इधर, उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 30 अप्रैल को होने वाले विशेष सत्र में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने 'आधी आबादी के संवैधानिक अधिकार छीनने का काम किया' और कांग्रेस शुरू से ही महिला आरक्षण का विरोध करती रही है। साव ने कहा कि इस सत्र के माध्यम से विपक्षी नेताओं की भूमिका को उजागर किया जाएगा।

30 अप्रैल को एक दिवसीय विशेष सत्र : छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 30 अप्रैल को प्रस्तावित है। इस दौरान राज्य सरकार महिला आरक्षण कानून और डिलिमिटेशन से जुड़े 131वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने के विरोध में निंदा प्रस्ताव ला सकती है। इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस के आसार हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वे 'दुखी मन' से अपनी बात रख रहे हैं। उनके मुताबिक महिलाओं को 33% आरक्षण देने का सपना विपक्ष के रुख के कारण पूरा नहीं हो सका। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से देश की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों को ठेस पहुंची है और यह केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

1 मई को रायपुर में मांस-मटन बेचने पर होगी कार्रवाई,बुद्ध जयंती पर बूचड़खाने रहेंगे बंद

रायपुर,28 अप्रैल 2026। रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में बुद्ध जयंती के अवसर पर 1 मई 2026, शुक्रवार को मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस दिन शहर के सभी पशुवध गृह और मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

जोन स्तर पर निगरानी : निगम प्रशासन के अनुसार, सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेंगे, ताकि प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

होटल में बिक्री पर भी कार्रवाई : महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर बुद्ध जयंती के दिन यदि किसी होटल या प्रतिष्ठान में मांस-मटन का विक्रय पाया गया तो तत्काल जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

पुलिस को चकमा देने की रची थी बड़ी साजिश,कांग्रेस ने कैश कांड मामले में पार्षद को पार्टी से किया सस्पेंड

रायपुर,28 अप्रैल 2026। राजधानी रायपुर में 50 लाख रुपए के चर्चित कैश कांड ने सियासत गर्मा दी है। कांग्रेस पार्टी ने सख्त कदम उठाते हुए बीरगांव नगर निगम के पार्षद ओमप्रकाश साहू को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई तब हुई जब पुलिस ने पार्षद को कारोबारी के 50 लाख रुपए ठिकाने लगाने और आरोपियों को संरक्षण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

ड्राइवर ने रची थी साजिश, पार्षद ने पुलिस के नाम पर खेला खेल : पूरा मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 25 अप्रैल को खम्हारडीह इलाके में एक कारोबारी के ड्राइवर कृष्णा साहू ने अपने ही मालिक को चूना लगा दिया। ड्राइवर बैंक में पैसे जमा करने के बहाने निकला और अकाउंटेंट को गुटखा लेने भेजकर 50 लाख रुपए और कार लेकर चंपत हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार,इस चोरी की रकम को सुरक्षित रखने के लिए पार्षद ओमप्रकाश साहू का सहारा लिया गया था। जांच में पुलिस के सामने चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर के जीजा ने पूरी रकम पार्षद ओमप्रकाश साहू को सौंप दी थी। पार्षद ने पुलिस से बचाने का झांसा देकर रकम अपने पास रखी। पुलिस को गुमराह करने के लिए पार्षद ने 15 लाख रुपए की फोटो खींचकर भेजी और दावा किया कि बस इतना ही मिला है। जबकि 20 लाख रुपए उन्होंने शातिर तरीके से छिपा दिए थे,जिसे पुलिस ने बाद में बरामद कर लिया। जैसे ही पार्षद की गिरफ्तारी की खबर फैली, रायपुर कांग्रेस में हड़कंप मच गया। जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) के अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे ने बिना देर किए निलंबन का आदेश जारी कर दिया।

छत्तीसगढ़ जनगणना ड्यूटी से इनकार नहीं कर सकेंगे कर्मचारी हाईकोर्ट का सख्त आदेश,इसे बताया 'राष्ट्रीय दायित्व'

रायपुर,28 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ में आगामी जनगणना कार्यों को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सख्त कानूनी फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत और नगर निकायों में कार्यरत कर्मचारी जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य से खुद को अलग नहीं कर सकते और न ही ड्यूटी करने से इनकार कर सकते हैं।

क्या है जनगणना का महत्व? कोर्ट ने अपने आदेश में साफ शब्दों में कहा है कि जनगणना एक 'राष्ट्रीय दायित्व' है, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या ड्यूटी से बचने की कोशिश कतई स्वीकार्य नहीं होगी।

ड्यूटी अनिवार्य : कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पंचायत और नगरीय निकायों के कर्मचारी जनगणना के कार्य के लिए बाध्य हैं। इस सरकारी काम से बचने का उनके पास कोई कानूनी विकल्प मौजूद नहीं है।

राष्ट्रीय कार्य को प्राथमिकता: अदालत ने जनगणना को देश का एक महत्वपूर्ण कार्य माना है, जिसके सुचारू संचालन के लिए सभी संबंधित सरकारी कर्मियों का सहयोग अनिवार्य है।

कानूनी बाध्यता : इस फैसले के बाद, अब जनगणना ड्यूटी पर तैनात किए गए कर्मचारियों को बिना किसी बहाने के अपना दायित्व निभाना होगा। इस कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करना अब कानूनी जटिलताओं को न्योता देने जैसा होगा।

प्रशासन के लिए बड़ी राहत : हाईकोर्ट का यह आदेश राज्य प्रशासन के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 1 मई 2026 से जनगणना का कार्य (मकान सूचीकरण और गणना) शुरू होने जा रहा है। ऐसे में कोर्ट की यह टिप्पणी स्पष्ट करती है कि प्रशासन को जनगणना कार्य को समयबद्ध और त्रुटिहीन पूरा करने में अब कर्मचारियों की ओर से किसी भी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा।

राजधानी में खून-खराबा,किशोर की चाकू मारकर हत्या

रायपुर,28 अप्रैल 2026। रायपुर एक बार फिर अपराध की आग में सुलग उठा, जब सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। 16 वर्षीय किशोर कुश बाघ की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि पंचशील नगर के जोगी मोहल्ला इलाके में सोमवार रात करीब 11:30 बजे से 12 बजे के बीच कुछ युवकों ने दोनों नाबालिगों पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने ताबड़तोड़ चाकू से वार किए, जिससे कुश बाघ की मौके पर ही मौत हो गई। घायल साथी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया,जहां उसका इलाज जारी है। घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे। बड़ी संख्या में लोग सिविल लाइन थाने पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए घेराव कर दिया। परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों डीएसपी सेंट्रल उमेश प्रसाद गुप्ता और एसीपी रमाकांत साहू ने स्थिति को संभालते हुए परिजनों को शांत कराने की कोशिश की।

श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस, ई-श्रम साथी एप लॉन्च

श्रमिकों के सशक्तिकरण की दिशा में तेज कदम,ई-श्रम साथी एप से मिलेगी नई गति : मुख्यमंत्री विष्णु देव

रायपुर,28 अप्रैल 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में श्रम विभाग के कार्यों और योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि मैदानी अमला पूरी प्रतिबद्धता के साथ श्रमिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि योजनाओं का वास्तविक प्रभाव तभी दिखाई देगा, जब उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जमीनी स्तर पर उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। इस अवसर पर श्रम मंत्री लखन देवांगन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में श्रमिकों के हित में व्यापक पहल हुई है और चार नई श्रम संहिताएं लागू की गई हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि श्रमिकों को सुरक्षित, संरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण मिल सके। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि श्रम विभाग एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है,जो बड़े पैमाने पर श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण भी तकनीक के माध्यम से किया जाए, ताकि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार के इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिल रही है।इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने श्रमिकों को घर बैठे रोजगार की जानकारी सहज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-श्रम साथीमोबाईल एप्लीकेशन छत्तीसगढ़ डिजिटल लेबर चौक का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की मेहनत देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है, इसलिए उनके योगदान का सम्मान और उनके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।समीक्षा बैठक में श्रम विभाग की संरचना, श्रमायुक्त संगठन, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवस्था तथा तीनों प्रमुख मंडलों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। प्रदेश के सभी जिलों में श्रम कार्यालयों के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन और समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि श्रमिकों को योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ दोनों सुनिश्चित हो सके। उल्लेखनीय है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत 5 सितंबर 2008 से अब तक 33 लाख 14 हजार से अधिक श्रमिक पंजीकृत किए जा चुके हैं। मंडल द्वारा 26 योजनाएं संचालित की जा रही हैं तथा 60 श्रमिक वर्ग अधिसूचित हैं। एक प्रतिशत उपकर (सेस) से वर्ष 2025-26 में 315 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि मंडल गठन से अब तक कुल 2,808 करोड़ रुपये का उपकर संग्रहित हुआ है।

114 युवाओं की उम्मीदें फिर जगीं : हाईकोर्ट ने एफसीआई भर्ती रद्द करने का आदेश ठहराया अवैध

बिलासपुर,28 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भारतीय खाद्य निगम की वर्ष 2017 की वॉचमैन भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह निरस्त करने के फैसले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस निर्णय को असंवैधानिक, मनमाना और अवैध बताते हुए विभाग को निर्देश दिया है कि संदिग्ध उम्मीदवारों को अलग कर शेष पात्र अभ्यर्थियों का परिणाम तीन महीने के भीतर जारी किया जाए। यह फैसला उन 114 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो पिछले सात वर्षों से नौकरी की उम्मीद में इंतजार कर रहे थे। हालांकि, अंतिम चरण में 47 उम्मीदवारों के हस्ताक्षरों में अंतर पाए जाने पर मामला विवादों में घिर गया। इसके बाद जांच के लिए प्रकरण फोरेंसिक लैब भेजा गया और पूरी भर्ती प्रक्रिया लंबित हो गई। करीब पांच वर्षों तक चली जांच के बाद 12 जनवरी 2023 को एफसीआई ने अचानक पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। इस फैसले से उन उम्मीदवारों की उम्मीदें टूट गईं, जिन्होंने पूरी प्रक्रिया ईमानदारी से पूरी की थी। इस निर्णय को चुनौती देते हुए मनीष कुमार यादव, खेम प्रसाद सहित अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब फोरेंसिक जांच में संदिग्ध और सही उम्मीदवारों की पहचान हो चुकी है, तो पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना न्यायसंगत नहीं है। कुछ लोगों की गलती का खामियाजा सभी अभ्यर्थियों को भुगतने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ईमानदार उम्मीदवारों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशासनिक निर्णयों में निष्पक्षता और पारदर्शिता अनिवार्य है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रभावित अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। कई उम्मीदवारों ने इसे 'न्याय की जीत' बताया और उम्मीद जताई कि अब उन्हें जल्द ही नियुक्ति मिलेगी।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)